[Shri A. C. George]

accommodation will be made in the national interest, in the interest of the industry, when we frame the rules. I may again assure the hon. House that the employees, the fishermen and people who are engaged in this field will always be given representation and due consideration.

SHRI K. GOPAL (Karur): The hon. Minister mentioned about 'big shots' Can he be more specific about it? It seems, monopolies like India Tobacco, D. C. M. and Britannia are trying to enter this field. Can the Minister be specific about the 'big shots'? May I also know whether definite steps will be taken to prevent people who have no connection whatsoever with this industry, entering the field?

MR CHAIRMAN He said that all consideration will be given to the suggestions made by the hon. Members and utmost care will be taken

Now, the question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted

— —

15 hrs.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd*

MR. CHAIRMAN: Now, we take up further consideration of the Motion of Thanks on the President's Address. Mr. Vajpayee

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): सभापति जी, राष्ट्रपति महोदय ने जिन शब्दों के साथ अपना अभिभाषण समाप्त किया है, मैं वहीं से प्रारम्भ करना चाहता हू "... महानता इस राष्ट्र का आवाहन कर रही है- वह महानता जो परम्परागत शक्ति-संचय द्वारा नही बल्कि आत्मिक बल से प्राप्त होती है।"

राष्ट्रपति महोदय के ये शब्द स्वयं मे बड़े मर्मस्पर्शी है इनमें निहित भाव अंतःकरण को आन्दोलित और अनुप्राणित करने की क्षमता रखते हैं। आत्मबल से प्राप्त होनेवाली महानता का आवाहन एक ही वाक्य में भारत के उज्ज्वल अतीत और उज्ज्वलतर भविष्य की झाकी प्रस्तुत कर देता है। भारत को महान बनना है इसमे सन्देह नही है। महानता हमारी नियति है, यह भी निर्विवाद है। हमारी महानता हथियारो के अम्बारों पर निर्भर नही होगी। यह भी एक ध्रुव सत्य है। लेकिन पता नही राष्ट्रपति के अभिभाषण मे महानता का आवाहन खोखला क्यो जान पड़ता है? मालूम नहीं आत्मबल का उल्लेख पाखंड क्यों प्रतीत होता है।

सम्भव है इसका एक कारण यह हो कि जब महानता के आवाहन का उल्लेख हो रहा था तब केन्द्रीय कक्ष मे, राष्ट्रपति महोदय के ही सम्मुख विदेशी राजनीतिज्ञो की साक्षी में इस सदन का सब से बडा विरोधी दल प्रधान मंत्री को लोकतन्त्र की हत्यारिणी और फासिस्ट कह रहा था। आवाहन महानता का हो रहा था और प्रदर्शन उच्छृंखलता का किया जा रहा था।

मार्क्सवादी मित्रों ने उस दिन जो कुछ किया उसकी प्रशंसा नही की जा सकती। उनका आचरण आपत्तिजनक था। पश्चिम बंगाल मे चुनावों मे धांधली के समाचार मे भी मिले है। पश्चिम बंगाल मे क्यो, अन्यत्र भी ऐसे तरीके अपनाए गए जिन के चलते चुनावों को सर्वथा निष्पक्ष और स्वतन्त्र नही कहा जा सकता। किन्तु यदि किसी दल को इस बारे में अपना रोष या आक्रोश प्रकट करना था तो उसका स्थान राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण नही था, उस दल के सदस्य अभिभाषण के बाद इस सदन में आकर अपनी बात कह सकते थे। जनतंत्र में कहीं न कहीं तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी।

किन्तु क्या सत्तारूढ़ दल ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया है? क्या उसका आचरण आदर्श रहा है? उस दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मध्य मे ही सत्तारूढ़ दल ने अपने को निर्वसन कर दिया। जब मार्क्सवादी सदस्य बाहर जाने लगे तो तालियां बज उठीं।

तालिया बजाने वाले पिछली बेंचों पर बैठने वाले ही नही थे। उनमे इस सदन की नेत्री, प्रधान मंत्री भी शामिल थी। वे तालिया कह रही थी-अच्छा हुआ, बला टली। बहुत अच्छा हुआ, मुसीबत मिटी। तालिया बजाने वालो के बाद चेहरो पर विषाद या ग्लानि की छाया नही थी। उनके चेहरो पर सात्विक आक्रोष का आवेग भी नही था। एक अभिमान पूर्ण मुस्कान थी, ऐसी अभिमानपूर्ण मुस्कान जो विरोध का आदर करना तो दूर रहा उसे सहन करने का भी सहिष्णुता नही रखती।

आह्वान महानता का और आचरण लघुता का इसका और दो उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक चुनाव के पहले का है, दूसरा बाद का। एक विजय की लालसा का है, दूसरा विजय के उन्माद का।

दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित नागरिको ने मयूर वाला हंसराज गुप्त के अभिनन्दन का समारोह आयोजित किया। यह समारोह राष्ट्रपति भवन मे होना था। समारोह की स्वीकृति ली जा चुकी थी, निमत्रण-पत्र बट गए थे, तैयारिया पूर्ण हो गई थी और कार्यक्रम 28 फरवरी को होना था। अचानक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और कहा गया कार्यक्रम चुनाव के बाद 20 मार्च को होगा। लेकिन जब 20 मार्च निकट आया तो कहा गया कार्यक्रम अप्रैल मे होगा किन्तु अप्रैल की कोई तिथि नही दी गई। समारोह का आयोजन करने वाले समझ गए कि सरकार को यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन मे हो, यह पसन्द नही है। यदि ऐसा था तो कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन मे आयोजित ही क्यो किया गया और यदि आयोजित कर लिया गया था, उसकी स्वीकृति दे दी गई थी तो क्या वह कार्यक्रम यदि राष्ट्रपति भवन मे हो जाता तो राष्ट्रपति भवन को पवित्रता को कलंक लग जाता? महानता की कसौटी पर इस आचरण को भी कसना होगा।

दूसरी घटना चुनावों के बाद की है। जयपुर मे जैन समाज ने नवनिर्वाचित विधान सभा सदस्यो के सम्मान मे एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमे अनेक दलो के सदस्य शामिल हुए। बाद मे सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से जवाब तलब किया गया कि जैन समाज के साम्प्रदायिक मच पर क्यो गए? जनसघ विधायको के साथ क्यो बैठे? क्या जैन समाज का मच साम्प्रदायिक मच है? मुस्लिम लीग के साथ गलबहिया डाल कर केरल मे प्रेम की पींगे भरने वाले जैन समाज को साम्प्रदायिक कहे, इससे बड़ी विडबना और क्या हो सकती है? जहा तक जनसघ वालो के साथ बैठने का प्रश्न है, क्या विरोध अब इस निकृष्ट और निम्न सीमा तक जायेगा? क्या सामाजिक क्षेत्र से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के बजाय हम राजनीतिक क्षेत्र मे नयी अस्पृश्यता का श्रीगणेश करना चाहते है? क्या हमारा हृदय इतना सकुचित और सकीर्ण हो जायेगा?

राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा है— महानता आह्वान कर रहा है। किन्तु महानता लाने का काम वे नही कर सकते जिनमे स्वय महानता का अभाव है। राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा है-महानता आत्मबल से प्राप्त होगी, किन्तु आत्मबल जगाना उनके बूते का नही है जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए आत्मबल के अतिरिक्त हर बल का उपयोग किया है।

क्या यह आश्चर्य का बात नही कि पश्चिम बगाल मे चुनाव के दौरान हुई हिंसा तथा ज्यादती का औचित्य यह कह कर सिद्ध किया जा रहा है कि मार्क्सवादियों ने भी तो इस प्रकार का हिंसा और जोरजबरदस्ती का आश्रय लिया था। मेरे मित्र स्टीफेन इस सदन मे मौजूद है—मुझे खेद है मै हिन्दी मे बोल रहा हू, उन्हे समझने मे कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उनके भाषण का एक अश मैं रखना चाहता हू। उन्होने मार्क्सवादियो को सम्बोधित करते हुए कहा था :

> "When you start stoning you must be prepared for being stoned back. When you start stabbing you must be prepared to receive the stab back."

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

मुझे उनका यह भाषण सुनकर खेद हुआ। इससे अधिक खेद मुझे प्रो० हीरेन मुकर्जी के भाषण का अश पढ़कर हुआ। प्रो० हीरेन मुकर्जी कम्युनिस्ट पार्टी मे है लेकिन उनका व्यक्तित्व किसी पार्टी की सीमा मे नही बाधा जा सकता शायद वातावरण का असर ऐसा है कि उन्हे भी यह बात कहनी पड़ी। मै उन्ही के शब्दों को उद्धृत कर रहा हू :

> "When violence is practised by certain people, it is all right, but when violence is practised by certain other people, it does not seem to be all right"

श्री स्टीफन और प्रोफेसर मुखर्जी, दोनो ने एक ही बात कही है कि पश्चिम बगाल मे जो कुछ हुआ ठीक हुआ क्योंकि मार्क्सवादियो के विरुद्ध वही हथकडे अपनाये गये जो मार्क्सवादियों ने पहले अपने विरोधियों के विरुद्ध अपनाये थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जायगा ? क्या हत्या का जवाब हत्या से दिया जायगा ? क्या आग को आग से बुझाया जायगा ? क्या महात्मा और मार्क्स के अनुयाइयों मे कोई अन्तर नही होगा? शिव को पूजते पूजते शिव बनने की बात तो शास्त्रों में कही गयी है, किन्तु मार्क्सवादियो से लडते लड़ते मार्क्सवादियो की सारी बुराइया अपने मे स्वीकार करने का दृश्य अभी दिखाई दे रहा है।

सभापति जी, यदि हिंसा को हिंसा से जीतने की बात है तो राष्ट्रपति के भाषण मे आत्मबल की चर्चा करना बेकार है। यदि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो आत्मबल की दुहाई देना व्यर्थ है। पशुबल की पूजा करने वालों को आत्मबल का राग अलापना शोभा नहीं देता। यह पाखड बन्द होना चाहिये। चुनाव जीत लिये गये, सत्ता पर एकाधिकार कर लिया गया, अब आत्मबल का अलख जगाने की क्या आवश्यकता है ?

सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने बांगला देश के संदर्भ में कहा है कि जब बांगला देश के साढ़े सात करोड़ लोगों की आजादी और जिन्दगी खतरे मे पड़ गयी थी तब संसार के लोग आगा पीछा कर रहे थे। क्या भारत सरकार स्वय आगा पीछा नहीं कर रही थी ? क्या आठ मास तक वह हाथ पर हाथ रख कर नही बैठी रही? क्या यह सच नही है कि अपनी गिरफ्तारी से पूर्व ही शेख मुजीबुर्रहमान ने नई दिल्ली को सदेश भिजवाया था कि यदि भारत अविलम्ब मान्यता देने को तैयार हो तो वह बागला देश को स्वाधीन घोषित कर देंगे। यह जानकारी मुझ बागला देश के एक नेता से प्राप्त हुई है, और मैं चाहूगा कि सरकार इस सम्बन्ध मे अपनी स्थिति को स्पष्ट करे।

चुनाव के दौरान बागला देश की मुक्ति का पूरा श्रेय प्रधान मत्री जी को देने का प्रयास हुआ। यदि मुक्ति का पूरा श्रेय उनको है तो कार्यवाही मे विलम्ब से जो लाखों लोगों की जाने गयी और हजारों बहनो की इज्जत लूटी गयी उसका कलक कौन लेगा ? चुनाव मे मुजीब की रिहाई का श्रेय सरकार ने लूटा, जबकि प्रधान मन्त्री को पता नही था कि शेख मुजीबुर्रहमान जीवित है या मृत। यहा तक कि जब समाचार आया कि मुजीब को लेकर हवाई जहाज अज्ञात स्थान को रवाना हो गया है तो उन्होंने लखनऊ मे कहा कि पता नही वह जिन्दा भी हैं या नही।

चूकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार को यह स्वीकार करने में सकोच नहीं होना चाहिये कि उसने बांगला देश में कार्यवाही करने में देर कर दी। गलतियां सबसे होती हैं, बड़े लोग बड़ी गलतियां करते है। किन्तु महानता का आवाहन करने वालों को उन्हे स्वीकार करने मे सकोच नही होना चाहिये।

भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, जनरल कुमारमंगलम राजनीति में नहीं हैं, और न उनकी गणना प्रधान मंत्री के विरोधियों में की जा सकती है। उनका भी कहना है कि भारत ने बांगला देश में देर कर दी। एक लेख में उन्होंने लिखा है :

"गत वर्ष की घटनाओं, यथा शरणार्थियों की भारी संख्या, उनके पुनर्वास की मंहगी कीमत, गत आठ महीनों में मारे गये निर्दोष लोगों की विशाल संख्या, अनियमित सैनिकों से शस्त्र वापस लेने का प्रश्न, सीमा के दोनों ओर गलत हाथों में शस्त्रास्त्र चले जाने की समस्या आदि आदि का जब मैं विचार करता हूं तो मैं अब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अप्रैल में कार्यवाही करना स्वयं हमारे लिये उपयुक्त रहता।"

जनरल कुमारमंगलम के विचार राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन उन्होंने एक विचार रखा है, एक दृष्टिकोण रखा है, उस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

सभापति जी, बांगला देश में कार्यवाही करने में देर की गयी है इसका उत्तर यह कह कर दिया जा सकता है कि बांगला देश ने अपनी आजादी स्वयं अर्जित की है, हमने उसे तश्तरी में रखकर उन्हें भेंट नहीं किया। मैं बांगला देश की जनता के त्याग और बलिदान तथा पराक्रम को कम करके देखना नहीं चाहता। यदि बांगला देश के निवासी स्वयं स्वाधीनता की आवाज न उठाते और उसके लिये संघर्ष न छेड़ते तो हम लोग इच्छा होने पर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते थे। किन्तु यह भी एक तीखा तथ्य है कि बिना भारतीय सेनाओं के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बांगला देश आजाद नहीं हो सकता था। इससे भी तीखा एक और तथ्य है कि बिना सोवियत समर्थन के हम इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे।

यह भी एक कटु सत्य है कि एक तरफा युद्धविराम के मूल में सोवियत दबाव काम कर रहा था। यदि सोवियत दबाव नहीं था तो यह बताया जाय कि युद्ध विराम में इतनी जल्दी क्यों की गयी? क्या इस भय के कारण कि यदि युद्ध लम्बा चला तो कोई तीसरी ताकत कूद पड़ेगी? मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध विराम का विचार सरकार के दिमाग में कब उपजा? ढाका के पतन और एक तरफा युद्ध विराम के एलान के बीच जो समय बीता उसमें साउथ ब्लाक में, मास्को में, वाशिंगटन में क्या हुआ? कौन से तार खटके? कौन सी नसें दबायी गयीं?

युद्ध विराम का औचित्य ठहराने के लिये यह कहना कि हम पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहते थे इसलिये हमने एकतरफा लड़ाई बन्द कर दी, हास्यास्पद है। जमीन तो हम बांगला देश की भी नहीं चाहते थे। किन्तु वहां हमने तब तक लड़ाई बन्द नहीं की जब तक पाकिस्तानी सेना ने हथियार नहीं डाल दिये। यह नीति पश्चिम में क्यों नही अपनायी गयी। हमारी बहादुर सेना 17 दिसम्बर को रात में 8 बजे शकरगढ़ पर अंतिम प्रहार करने के लिये तैयारी कर रही थी। किन्तु उसी समय से युद्ध विराम लागू हो गया।

आज कहा जाता है कि संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। यह भी कहा जाता है कि जनता को जागते रहना चाहिये। किन्तु प्रश्न यह है कि पाकिस्तान को नया संकट पैदा करने लायक छोड़ा क्यों गया? पश्चिम में उसकी पराजय के लिये पग क्यों नहीं उठाये गये? यदि पाकिस्तान पुनः शरारत करता है तो इसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी जिसने लड़ाई बन्द करने में जल्दबाजी दिखाई। जनरल मानेकशा ने कहा है कि यदि लड़ाई 5 दिन और चलती तो पाकिस्तान 25 साल के लिये ठंडा पड़ जाता।

सभापति जी, लड़ाई के मैदान में सेनायें खरी उतरीं, किन्तु कूटनीति के क्षेत्र में नेतृत्व की परीक्षा बाकी है। मैं चाहता हूं कि सरकार युद्ध बन्दियों की वापसी और जीते हुए क्षेत्रों को लौटाने के बारे में अपना मौन भंग करे, इस सदन को विश्वास में ले, देश को और अधिक अंधकार में न रखे।

जब से पाकिस्तानी राष्ट्रपति मास्को से लौटे हैं यह चर्चा चल पड़ी है कि क्रेमलिन

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

चाहता है कि भारत युद्ध बन्दियों की वापसी के प्रश्न को अन्य भारत-पाक सवालों के साथ न जोड़े । मैं नही जानता इसमें कहां तक सच्चाई है ? लेकिन अगर यह सच है तो यह बड़ी गम्भीर बात है और इस बात का संकेत है कि युद्ध के दौरान अपने ताश के सारे पत्ते भारत के पक्ष में रखने वाला रूस अब पुनः ताश खेलने की तैयारी कर रहा है और ताशकन्द की ओर आगे बढ़ रहा है ।

जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्ध बन्दियों की वापसी तभी हो सकती है जब शान्ति की संधि हो जाय । किन्तु शान्ति की सन्धि तो दूर पाकिस्तान सेसेशन आफ ऐक्टिव हौस्टिलिटीज के लिए भी तैयार नही है । श्री भुट्टो ने प्रधान मंत्री के युद्ध न करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है । वह काश्मीर पर आत्म निर्णय की रट लगाये जा रहे है । कभी युद्ध की धमकी देते है, कभी शान्ति का राग अलापते है । एक सांस में ठंडा और गर्म उगलते हैं । भारत को उनके झांसे मे नही आना चाहिये । युद्ध बन्दियों की वापसी का प्रश्न अन्य सवालो से अलग करके नहीं देखा जा सकता । अन्य सवाल हैं :

एक तिहाई काश्मीर की वापसी, काश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण की समाप्ति, युद्ध में और विस्थापितों की देख भाल पर जो खर्चा हुआ है उसका हर्जाना, निष्कान्त सम्पत्ति का निबटारा और 300 करोड़ रुपये के पुराने ऋण की अदायगी । इसके साथ ही पाकिस्तान को बंगला देश के पुनर्निर्माण का खर्चा भी उठाना होगा ।

श्री भुट्टो इस समय कठिनाई में हैं । वे चाहते हैं कि भारत उनको कठिनाई में से निकाले । हमने उन्हें कठिनाई में नहीं फंसाया । वे स्वयं कठिनाई में फंसे हैं । लेकिन उन्हें कठिनाई में से निकालने के लिए भारत को स्वयं कठिनाई में नहीं डाल सकता । आज पाकिस्तानी राष्ट्रपति मानवता की बात कर रहे हैं । भुट्टो और मानवता ? दोनों में दूर का भी नाता नहीं है । जब बंगला देश में मानवता की हत्या की गई तब श्री भुट्टो याहिया खां के साथ ही थे । आज वे स्वयं को दूध का धुला साबित करना चाहते हैं । श्री भुट्टो भविष्य में क्या कर सकते है, इसको समझने के लिए उन्होंने अतीत में क्या क्या किया था, इसको स्मरण कर लेना काफी है ।

प्रश्न यह नहीं है कि हमें युद्ध बन्दियों को छोड़ना चाहिये या नहीं छोड़ना चाहिये । प्रश्न यह है कि क्या हम युद्ध बन्दियों को छोड़ सकते है ? क्या हम सुरक्षा को खतरे मे डाल सकते हैं ? क्या बिना शान्ति की स्थायी सधि हुए केवल भुट्टो को बचाने के लिए हम युद्धबन्दियों के सवाल को अलग करके देख सकते हैं ? भारत को पूरा अधिकार है कि युद्ध बन्दियों के सवाल को स्थायी शान्ति की सधि के साथ जोड़े । यह हमारी सुरक्षा का मामला है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी हमारे पक्ष में है । सरकार को परीक्षा की इस घड़ी मे कमजोरी नही दिखानी चाहिये । युद्ध के मैदान मे जो कुछ जीता गया है, उसे वार्ता की टेबल पर नही गंवाया जा सकता ।

पाकिस्तानी युद्धबंदी भारत और बंगला देश दोनों के युद्ध बंदी है । उन्होंने संयुक्त कमान के सम्मुख आत्मसमर्पण किया है । पाकिस्तान के साथ युद्ध बदियों के बारे मे वार्ता द्विपक्षीय नहीं होगी, त्रिपक्षीय होगी । जब तक पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता नहीं देता, ढाका उसके साथ वार्ता कैसे कर सकता है ।

जेनेवा कन्वेंशन 1949 का आर्टिकल 119 हमें तथा बंगला देश को अधिकार देता है कि जिन बन्दियों के विरुद्ध अभियोग है, उन पर मुकदमे चलायें और सजा पूरी होने तक उन्हें अपनी कैद में रखें । यदि श्री भुट्टो वस्तुतः सम्बन्धों को सामान्य बनाना चाहते है तो उन्हें संकेत के तौर पर एक छोटा सा काम करना चाहिये । उन्हें जनरल टिक्का खां को

बंगला देश को सौंप देना चाहिये जिससे हलाकू और हिटलर को मात करने वाले उस कसाई को कटघरे मे खड़ा किया जा सके। यदि श्री भुट्टो ऐसा नही करते है तो समझ लेना होगा कि उनके शान्ति प्रयास एक धोखा है। जैसे ही युद्ध बंदी रिहा हुए और पाकिस्तान की धरती पर पहुचे, श्री भुट्टो अपना रंग बदल जाएगे। हमे सोवियत रूस को भी समझाना चाहिये कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका के चगुल मे जाने से रोकने के लिए वह भारत की कीमत पर इस्लामाबाद से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास न करे। यह 1972 है, 1965 नही। सरकार ताशकद की पुनरावृत्ति नही होने देने की घोषणा मे बधी हुई है। सरकार को अपने वचनों से मुकरने नही दिया जाएगा। जनता जवानो के बलिदान पर पानी नही फिरने देगी।

चुनाव परिणामो ने प्रधान मन्त्री के हाथो मे असाधारण शक्ति और अधिकार रख दिए हैं। ब्रिटेन के एक पत्र ने उन्हे भारत की साम्राज्ञी के रूप मे पेश किया है। अब स्थिति यह है कि सारी सत्ता नई दिल्ली मे केन्द्रित हो गई है। प्रदेशो के मुख्य मंत्री नई दिल्ली के इशारो पर चलते है। केन्द्रीय मंत्री दिल्ली के दरबार मे दरबानो से अधिक हैसियत नही रखते। लाला दुर्गा दास एक प्रसिद्ध पत्रकार है। उन्होने, मंत्रिमडल मे परिवर्तन की जो चर्चा हो रही है, उस पर टिप्पणी करते हुए कुछ लिखा है, उसका मै उद्धृत करना चाहता हू। वह कहते हैं :

> "The upper strata of bureaucracy is convinced that whoever be the new master, all decisions of consequence will have to get clearance from the Prime Minister's Secretariat."

प्रधान मंत्री का सचिवालय एक समानान्तर मंत्रिमंडल बन गया है। लेकिन इसमे कोई आश्चर्य की बात नही है। जब सारी सत्ता दो हाथो मे केन्द्रित हो तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। किन्तु ससदीय लोकतन्त्र की दृष्टि से इसे स्वस्थ विकास नही माना जा सकता। मंत्री जनता के प्रतिनिधि है। वे इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन उनके सचिवो के सम्बन्ध मे यह बात नही कही जा सकती।

शिखर पर खड़ी प्रधान मंत्री और उनके चरणो मे पड़े उनके सहयोगियो के बीच एक खाई पैदा हो गई है। एक पावर गैप है। उसे कैसे भरा जाएगा? क्या यह स्थिति एक व्यक्ति की तानाशाही के कायम होने का खतरनाक सम्भावनाओ से भरी हुई नही है? प्रधान मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई खतरा नही है। उन्ही के शब्दो का मै उद्धृत करना चाहता हू :

> 'We (the Congress) had similar power many years before also Fascism could have developed then, if it had to, but it did not."

यदि फैसिज्म आना होता तो पहले भी आ सकता था। लेकिन तब नही आया। लेकिन तब और अब मे एक अन्तर है। तब साध्य के साथ साधना की पवित्रता पर भी बल दिया जाता था। उस समय यह भरोसा था कि जैसी भी स्थिति हो कुछ जीवन मूल्यो की बलि नही चढाई जाएगी। यह विश्वास था कि कैसी भी उत्तेजना हो, कमर के नीचे वार नही किया जाएगा। आज स्थिति सर्वथा भिन्न है। प्रधान मंत्री के प्रशसक तथा विरोधी दोनो इस बात को जानते है कि अपने उद्देश्यो की पूर्ति के लिए प्रधान मंत्री कुछ भी कर सकती हैं। इसी मे उनकी सफलता का रहस्य है। लेकिन इसी मे लोकतन्त्र के विनाश के बीज छिपे हुए है।

आज नई दिल्ली की हवा मे घुटन है, उन्मुक्त सास लेना सरल नही है। विरोध की आवाज उठाना बगावत समझा जाता है। जिसे देखा वही कमिटमेंट का बिल्ला लगाए घूम रहा है। किसके लिए कमिटमेंट? एक व्यक्ति के लिए या एक दल के लिए ....

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : सोशलिज्म।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : या सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए। मेरे मित्र श्री शशि भूषण कहते हैं प्रतिबद्धता चाहिये। सोशलिज्म के लिए। कौन सा सोशलिज्म ? एक सोशलिज्म कम्युनिस्ट देशों में भी है, लेकिन वहां व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं है। दुनिया में अनेक महान ऐसे देश हैं जिनमें जाने पर पहली बात यह कही जाती है कि अगर सरकार की आलोचना करनी है तो होटल के कमरे में बैठ कर मत करो, बाग में जा कर करो, हो सकता है कि होटल के कमरे में ऐसे यंत्र लगे हों जिनसे बातचीत को रिकार्ड किया जा सकता है। दुनिया में ऐसे समाजवादी देश भी है जहां साहित्यकारों पर मुकदमे चल रहे है, जहा कोई अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति नही कर सकता है, जहां सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती है। हम कैसा समाजवाद चाहते है, यह स्पष्ट होना चाहिये।

कुछ साहित्यकारों ने जिनमें श्री जे० स्वामीनाथन, निर्मल वर्मा, एम० गोविन्दन, श्रीकान्त वर्मा, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश, रघुवीरदयाल आदि प्रतिष्ठित साहित्यकार, लेखक तथा पत्रकार शामिल हैं, एक वक्तव्य निकाल कर शिक्षा मंत्रालय को इस बात पर आड़े हाथों लिया है कि उसने दिसम्बर, 1971 में लेखकों कलाकारों तथा अन्य बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में हुए निर्णयों को तोड़मरोड़ कर प्रकाशित किया। मैं उनके वक्तव्य को विस्तार के साथ उद्धृत करना चाहता हूं। यह कन्वेंशन शिक्षा मंत्रालय ने बुलाया था। उस पर टिप्पणी करते हुए गण्यमान्य लेखक कहते है :

> "While the invitees to this convention were given to understand that a declaration will be formulated and adopted after a free and frank discussion, they were presented with a ready made draft full of sycophancy and political jargon. Even the amendments proposed and accepted to this draft were not incorporated in it and the draft itself was published and circulated by the Ministry of Education in the name of the participants. The declaration commits the Indian intellectuals to 'a solemn pledge' to unite in a so-called broad national cultural front and to use their creative talent for the realisation of certain political concepts. This attempt at defining creative commitment and subjugating it to the idea of a national cultural front is to say the least questionable in our democratic and pluralistic society. The use of the State bureaucratic machinery makes it all the more reprehensible."

अन्त मे लेखक कहते हैं :

> "During the last two decades a coterie of conformist intellectuals has emerged around various committees and cultural bodies and other Government aided institutions whose interests do not reflect in any way either the creative needs of the mass of intelligentsia or the cultural aspirations of the Indian people."

क्या यह आने वाली घटनाओं का संकेत है ? क्या प्रतिबद्धता के नाम पर चिन्तन की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता को रुद्ध किया जायेगा ? यदि ऐसा होता है, तो फिर लोकतंत्र के लिए जरूर खतरा पैदा होगा।

प्रधान मंत्री गरीबी हटाने चली थीं, किन्तु उन्होंने प्रतिपक्ष को हटाने में सफलता पाई है, जबकि गरीबी जहा की तहां है। मंहगाई बढ़ रही है। बेकारी काबू के बाहर जा रही है। विकास की दर गिर रही है। अन्न के मामले में आत्म-निर्भरता के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी है।

प्रश्न यह है कि गरीबी कैसे हटेगी। अभी प्रधान मंत्री जी एफ० आई० सी० सी० आई० के अधिवेशन में बोलने के लिए गई थी। मैंने उनका भाषण पढ़ा है। उसका एक अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

> "I must confess the path is not at all clear. We can make the path and bring about a qualitative change through your co-operation."

रास्ता स्पष्ट नहीं है, हम नया रास्ता बना सकते हैं, यदि इसका अर्थ यह है कि प्रधान मंत्री बंधी बंधाई लकीर पर नहीं चलना चाहतीं,

तो इसी में से संतोष निकाला जा सकता है। लेकिन यदि इसका अर्थ यह है कि क्या करना है, यह साफ नहीं है, और अगर कुछ नहीं किया गया और विरोध की आवाज उठी, तो अगर उसे यह कह कर दबाने की कोशिश की जायेगी कि यह प्रतिक्रियावाद की आवाज है, तो फिर यह लोकतंत्र के लिए एक गम्भीर खतरे का सूचक है।

क्या देश मे आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद नही होगा ? क्या गरीबी हटाने का एक ही मार्ग हो सकता है ? क्या समृद्धि लाने के रास्ते अलग-अलग नही हो सकते ? क्या लोकतत्र में प्रमाणिक मतभेदों के लिए गुंजायश नही होगी ? जो भी विरोध करेगा, वह प्रतिक्रियावादी है और जो भी हां मे हा मिलायेगा, वह प्रगतिवादी है, वह कौन सी कसौटी है ? व्यक्तियों को नापने का यह कौन सा गज है ? क्या यह काग्रेस पार्टी की शब्दावली है ? मेरे मित्र, श्री चन्द्रजीत यादव, यदि यह शब्दावली बोलें, तो मैं समझ सकता हू। लेकिन यह शब्दावली लोकतत्र में नहीं चल सकती।

श्री शशि भूषण : जनसघ मे नही चल सकता।

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : इनकी समझ मे नही आयेगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : पता नहीं, किसकी समझ मे आ रहा है, किसकी समझ मे नही।

प्रधान मत्री जी ने एफ० आई० सी० सी० आई० की सभा में यह भी कहा कि हमे तीन चार साल में कुछ करके दिखाना होगा, अन्यथा हम सभी को उखाड़ फेंका जायगा। अभी से उखाड़ फेंकने की बात शुरू हो गई है। अभी तो प्रधान मंत्री चुनाव में जीती है। अब तो उन्हें कुछ करने का अवसर मिला है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। उद्योगपतियों से यह कहने का क्या अर्थ है कि अगर कुछ नहीं किया तो उखाड़ फेंका जायेगा ? जनता ने प्रधान मंत्री और उनके दल को कुछ करने की शक्ति दी है। अब वे कुछ करके दिखायें।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहूगा। तीन चार साल का समय लम्बा है। जनता इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। एक साल के भीतर कुछ करके दिखाना होगा। तीन काम हैं। बेरोजगारों को रोजगार, बेजमीनों को जमीन और बेघरों को घर। यदि इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ, तो, जैसा कि प्रधान मत्री जी ने कहा है, परिणाम भयंकर होंगे। किन्तु परिणाम लोकतंत्र के लिए भयंकर नहीं होंगे। जिनके हाथ मे सत्ता है, उनके लिए परिणाम भयकर हो सकते हैं। जहां तक लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, हम उसकी रक्षा के लिए लड़ेंगे और किसी भी कुर्बानी को बड़ा नही समझेंगे।

सत्तारूढ़ दल को प्रचंड बहुमत मिल गया, किन्तु फिर भी दलबदल का खेल जारी है। अब तो दल-बदल समाप्त हो जाना चाहिए। स्थिरता की बात करने वालों को राजनीति में कुछ स्थिरता का समावेश करना चाहिए। आज भी प्रतिपक्ष मे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हू कि जब तक दल-बदल को रोकने का कानून नहीं बनता, सत्तारूढ़ दल को ऐलान कर देना चाहिए कि न तो वह दल-बदल को प्रोत्साहन देगा और न वह दल-बदल करने वाले किसी व्यक्ति को अपने दल में प्रवेश देगा। यदि दल-बदल में सत्तारूढ़ दल का कोई निहित स्वार्थ नहीं है, तो उसे स्वयं पर इस प्रकार की रोक लगाने मे कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

राजनीति पर पूंजी हावी हो गई है। चुनाव इतने खर्चीले हो गये हैं कि कोई व्यक्ति अपने बल-बूते पर चुनाव नहीं लड़ सकता। लक्ष्मीपुत्रों की कृपा के बिना कोई भी दल चुनाव नही लड़ सकता। इस बार के चुनाव में इतना ही नहीं कि पूंजीपतियों से पैसे लिए गये, पूंजी-

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]
पतियों को यह भी कहा गया कि इस दल को पैसा मत देना, अगर उसको पैसा दिया, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा।

श्री शशि भूषण : फिर भी ले लिया।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हम चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक जा सकते है, यह इसकी थोड़ी सी झलक है। आवश्यक है कि चुनाव कानून में क्रान्तिकारी संशोधन किये जायें। चुनाव कानून में संशोधन के लिए एक कमेटी बनी थी। उसने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। हम पश्चिमी जर्मनी का तरीका अपना सकते है, जहां चुनाव का अधिकांश व्यय सरकार वहन करती है। यह व्यवस्था महंगी है। लेकिन लोकतंत्र भी कोई सस्ती प्रक्रिया नहीं है। यदि लोकतंत्र की पूंजी के प्रभाव से विकृत होने से रोकना है तो इस दिशा में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। यह ठीक है जिनके पास सत्ता है वह धन जितना चाहे बटोर सकते है, जिनके पास धन है वह धन जितना चाहे बांट सकते हैं। लेकिन इससे जनमत का स्पष्ट प्रकटीकरण नहीं होगा। "यह भी आवश्यक है कि ऐसी स्वस्थ परम्पराएं डाली जाय जिसमे चुनाव दो दलों के बीच मे हो, दल और सरकार के बीच में न हो। चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़े, हम सरकार से लड़े। हैलीकोप्टर, वायुयान, आल इंडिया रेडियो पर प्रभात से ले कर रात्रि तक प्रधान-मंत्री के नाम का पारायण, सिनेमा के पर्दे पर प्रचार की पराकाष्ठा, प्रतिपक्ष में बैठने वाले दल का इसका मुकाबिला कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हू इसके लिए यदि सत्तारूढ़ दल में से ही आवाज उठती है और उठेगी तो स्वस्थ परम्पराएं डाली जा सकती हैं। क्या आल इंडिया रेडियो पर सब दलों को समय नहीं दिया जा सकता? क्या वाहनों की सुविधा सब दलों को उपलब्ध नहीं की जा सकती? लोकतंत्र परम्पराओं से चलता है। आज आप के हाथ में सारी शक्ति आ गई। मोनोपली हर क्षेत्र में खराब है मगर सत्ता की मोनोपली खराब नहीं है, उसका हमारे मित्र स्वागत करेंगे? लेकिन इतनी सत्ता आई है तो जिम्मेदारी भी आई है कि कुछ अच्छी परम्पराएं डालिए।

सभापति जी, हरयाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध 102 विधायकों ने राष्ट्रपति जी को एक स्मृति-पत्र पेश किया। संसद् सदस्यों ने भी उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की। मगर जांच नहीं कराई जा रही है। पंजाब में अकाली दल के मंत्रियों के विरुद्ध जांच आरम्भ हो गई। बन्दोदकर के खिलाफ प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप में निन्दात्मक शब्द कहे . .

एक माननीय सदस्य : सदन में उन्होंने इसका खण्डन किया कि नहीं कहे उन्होंने ऐसे शब्द।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अगर खण्डन किया तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मैं सदन में नहीं था। मुझे पता नहीं।

लेकिन चौधरी बंसी लाल के खिलाफ सब प्रमाण और भ्रष्टाचार के तथ्य राष्ट्रपति को समर्पित करने के बाद भी जांच न करने का कारण क्या है? क्या कारण है कि भ्रष्टाचार हरयाणा की परिधि को पार कर के नई दिल्ली को भी स्पर्श करने लगा है? मेरा निवेदन है कि जो सत्ता मिली है उसमें भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अपने भी दल का व्यक्ति हो तो उसके विरुद्ध प्रधान मंत्री को कठोर रवैया अपनाने के लिये तैयार रहना चाहिए।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : कुछ बजट पर भी बोलिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह बजट नहीं है। उनको यही पता नहीं कि किस चीज पर चर्चा हो रही है। वह कह रहे हैं कि बजट

पर बोलो। यह बजट नहीं है, राष्ट्रपति का अभिभाषण हैं।

राष्ट्रपति जी, मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। मेरे पास शिकायतें आई हैं आंध्र में नेशनल डिफेंस फंड एकत्र करने में अनियमितता बरती गई है। मुझे आंध्र में नेशनल डिफेंस फंड की ऐसी रसीदें दिखाई गयीं जिन पर कोई नम्बर नहीं था। रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। बिना नम्बर की रसीदें बांटी जा रही है। रुपया राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जा रहा है या किसी के व्यक्तिगत कोष में जा रहा है? मैंने ऐसी भी रसीदें देखी कि जिन पर डा० संजीव रेड्डी के दस्तखत है, वह काट दिए गए, ब्रह्मानन्द रेड्डी के दस्तखत है उन्हें भी काट दिया गया और फिर आज के मुख्य मंत्री नरसिंह राव के दस्तखत की मोहर है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा निधि वसूल करने जाते हैं और नई रसीदें नहीं छपा सकते? मैंने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा वित्त मंत्री श्री चह्वाण को। उन्होंने उत्तर दिया कि यह मामला मेरे अधीन नहीं है, प्रधान मंत्री जी के अधीन है। और प्रधान मंत्री जी को पत्र का उत्तर देने का समय नहीं है। मैं जानता हूं उनके ऊपर बहुत बोझ है। मगर नियति ने, भाग्य ने लोकतंत्र के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का भार भी प्रधान मंत्री के हाथों में रख दिया है। आज वह कसौटी पर कसी जा रही है। देखें यह सरकार खरी उतरती है या नहीं? .....
(*Interruption.*)

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): On a point of information for him.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am not yielding.

SHRI K. SURYANARAYANA: Through you, I want to tell him for his information....

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको बोलना हो तो बाद में बोलें। उन्होंने मेरे विचारों की धारा तोड़ दी। वह शायद आन्ध्र की सफाई दे रहे थे। मगर मैं आन्ध्र को छोड़ कर नई दिल्ली में आ गया हूं। मुख्य मंत्री का विचार मत कीजिए, प्रधान मंत्री की चर्चा कीजिए। भाग्य ने उनके हाथ में असाधारण अधिकार रख दिए हैं। लोकतंत्र को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता उनके पास आ गई है। वह कसौटी पर कसी जा रही है। यह सरकार परीक्षा में से गुजर रही है। चुनाव में कौन दल हारा, इसका बड़ा महत्व नहीं है। हम लोकतंत्रवादी हैं, चुनाव का निर्णय स्वीकार करते हैं। लेकिन आज किसी दल का भविष्य दाव पर नहीं लगा है, लोकतंत्र का भविष्य दांव पर लगा है। यदि हम लोकतंत्र को चिरस्थायी बना सके तो फिर राष्ट्रपति का महानता का आह्वान कुछ सार्थकता रख सकता है। यदि आत्म-बल की केवल बात करना ही है और आत्म-बल का आचरण नहीं करना हैं तो यह पाखंड राष्ट्र का निर्माण नहीं करेगा, यह पाखंड राष्ट्र के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा।

SHRI K. SURYANARAYANA: With your permission, I want to enlighten the House on one point. Shri Atal Bihari Vajpayee has referred to the issue of receipts for the National Defence Fund with the signature of Shri Sanjiva Reddy and other friends. The Andhra Government has recently announced that those receipts also were valid. They have already accounted for them. The Chief Minister has also contradicted this, but the House may know that these are accounted for.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The hon. Member has accepted that there are receipts without numbers. That was the point which I wanted to make. He has confirmed it.

SHRI C. M. STEPHEN: I wanted to make a submission by way of personal explanation. My hon. friend, Vajpayeeji, when he was speaking, misrepresented me and my speech......

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I quoted from your speech.

SHRI C. M. STEPHEN: .....as an attempt to defend violence and conceding that there was violence on our part. I only want

[Shri C. M. Stephen]

to clarify the position so that it is on record. What I said was, "Assuming but without conceding"; assuming for argument's sake that there was violence, I said that anybody else might have any complaint but the Marxist Communist Party, which is believing in violence [*An Hon. Member*: No.] and is propagating violence, had absolutely no right to complain about violence. That is what I said. And I said that for the Marxist Communist Party, who say that they stand by Mao's doctrine of power by the barrel of the gun, to come and wail that there was violence against them was cowardice. That is what I said. This was the point I made. I never conceded that there was violence on our part and I never defended the Government for that. I only said, "Assuming but not conceding."

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I accept his explanation.

डा० कैलाश : मैंने बजट की बात कही थी, वह सबकी गलतियां निकाल रहे थे, मैंने कहा कि कुछ बजट पर भी बोलें, बजट की भी गलतियां निकालें, तो हंसने लगे ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिये खड़ा हुआ हूं । यह अनुमोदन मैं इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं, बल्कि मैं यह महसूस करता हूं कि पिछले वर्ष सरकार ने जो कुछ किया है, उससे हमारे राष्ट्र की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, वह पुनः प्राप्त हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका सम्मान और गौरव बढ़ा है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है । इसके लिये हमारी फौजें, हमारे जवान, हमारे देश के अफसरों के तो हम ऋणी हैं ही, लेकिन हम जनता के सहयोग के भी आभारी हैं । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सही कहा है कि राजनीतिक राजनयिक तथा सैन्य सम्बन्धी नीति और निर्णय में सरकार ने जो विवेक और नेतृत्व का परिचय दिया है, प्रशासन के सभी स्तरों पर जो प्रभावकारी कार्य संचालन हुआ, उसके लिये सरकार और उसकी नेता इन्दिरा जी बधाई के पात्र हैं ।

अभी इस सम्बन्ध में हमारे विरोधी दल के नेता श्री अटल बिहारी जी बाजपेयी फरमा रहे थे कि सरकार ने बंगला देश के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया, उसने विलम्ब किया । उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों लोगों की जानें गई और देश को बहुत बड़ा आर्थिक बोझा उठाना पड़ा । यद्यपि श्री अटल बिहारी जी इस समय सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिया, उसकी परिपक्वता के बारे में वह निर्णय कसौटी पर खरा उतरा है, यह घटनाचक्र ने सिद्ध कर दिया है । यदि अटल बिहारी जी और इनके दल की सरकार होती और इन्होंने बंगला देश की मान्यता का जो नारा दिया था, यदि उस वक्त सरकार ने ऐसा किया होता तो मैं यह कह सकता हूं कि शायद देश का बेड़ा गरक हो गया होता । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि भले ही . . ..

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में गण-पूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घन्टी बज रही है..... अब कारम हो गया है । आप अपना भाषण जारी रखें ।

15.55 hrs.

[SHRIMATI SHEILA KAUL *in the Chair*]

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं कहना चाहता हूं कि महानता की बात करने वाले अटल बिहारी जी खुद जरा अपने दिल पर हाथ रख कर टटोलें । आज वह कहते हैं कि देश के गौरव का बखान नहीं हो सकता जो इन्दिरा जी ने बढ़ाया है, इसको वह स्वीकार नहीं कर सकते और इसीलिये वे इधर-उधर की बातें करके देश का ध्यान बंगला देश में जो हमारी

नीति की सफलता रही है, उससे हटाना चाहते हैं। वह अभी फरमा रहे थे कि जब बंगला देश की लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के बाद शान्ति स्थापना की एक-तरफा घोषणा क्यों की गई। वह यह भी कह रहे थे—मानेकशा और दूसरे लोगों के स्टेटमेन्ट्स को काट करते हुए—यदि पांच दिन बंगला देश और पश्चिमी पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ाई और चलती होती तो पाकिस्तान की सैन्य-शक्ति चकनाचूर हो गई होती। मैं कहना चाहता हूं—अटल बिहारी जी और उन जैसा सोचने वाले उनके दल के सब सदस्यों से—बंगला देश के बारे में हमारी जो भावना थी, उसका एक निश्चित कार्यक्रम था। हम बंगला देश में इसलिए नहीं गये थे कि हम पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते थे, हम पाकिस्तान की सैन्य-शक्ति को भी तोड़ना नहीं चाहते थे। हमारा उद्देश्य था—बंगला देश में प्रजातन्त्र और दूसरे जो सिद्धान्त है, उनकी रक्षा करना। हमने बंगला देश को आजाद करा कर हमारा जो सिद्धान्त था, उसको पूरा किया। और उसको पूरा करने के बाद हमारा इरादा पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस-नहस करने का नहीं था, हमारा इरादा लिमिटेड था, हम विस्तारवादी नीति के समर्थक नहीं थे, इसीलिये जब हमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, तो हमने पश्चिमी पाकिस्तान में युद्ध बन्दी की घोषणा कर दी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि युद्धबन्दी की घोषणा को, उसकी खूबसूरती को यह कह कर खत्म कर दिया जाए कि रशियावालों ने हम पर दबाव डाला, इसलिये इन्दिरा जी ने मजबूर होकर युद्ध-बन्दी की एकतरफा घोषणा की, इस तरह की बातें विरोधी दल के एक सम्मानित नेता को शोभा नहीं देती हैं। इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ने के बजाय घटती है। यह दलों का सवाल नहीं है, यह राष्ट्र का सवाल है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अटल जी जहां महानता की बात करते हैं, उन्हें महानता का आचरण भी करना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोफेसर दण्डवते और अटल जी ने चुनावों की चर्चा करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सन्देह व्यक्त किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं—हमारे देश में भले ही कुछ भी कहा जाय, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया के सबसे बड़े इस प्रजातन्त्र में जितनी निष्पक्षता से चुनाव होते हैं और होते आये हैं, दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में नहीं हुए हैं और इसके लिये हमारी सरकार मुबारकबाद की हकदार है। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से, सभापति जी, एक बात और कहना चाहता हूं—इस देश में सन 1947 में कांग्रेस को सत्ता मिली, कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त करने के बाद 26 जनवरी, 1950 को जनता के हाथों में दे दी। इन चुनावों के परिणामस्वरूप अगर कोई बात सिद्ध हुई है तो यह सिद्ध हुई है कि लोकतन्त्र जनता के हाथों में सुरक्षित है। भले ही आज हमारे विरोधी दल के लोग यह कहें कि आज इन्दिरा जी के पास अपरिमित शक्ति आ गई है, आज वह डिक्टेटर होने जा रही है, भले ही आज इन्दिरा जी के बारे में राज-दरबार की संज्ञा दी जाय लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बातों को करके हमारे विरोधी दल के दोस्त सही स्थिति को जांचने से भी जा रहे हैं। असल बात यह है कि विरोधी दल के लोग अपनी कमजोरियों को खुद पहचानना नहीं चाहते, उनको समझना नहीं चाहते। खुद उनका जो विरोध है वह अनप्रिंसिपल्ड है, उनका कोई सिद्धान्त नहीं है। अनप्रिंसिपल्ड विरोध करने वाले लोगों की यही गति होती है। मैं चाहूंगा कि वे स्वीकार करें इस बात को कि उन्होंने गल्तियां की हैं, जनता उनको रिजेक्ट करती है, जनता उनको पसन्द नहीं करती है और उसका दोष देते हैं इंदिरा जी पर और इंदिरा जी के साथ-साथ कांग्रेस दल पर। मैं कहना चाहता हूं कौन रोकता है आपको? आप आत्मनिरीक्षण करें, अपनी गल्तियों को पहचानें, अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करें। यह सही है कि देश में स्वस्थ प्रजातन्त्र के लिए, स्वस्थ सरकार के लिए मजबूत विरोधी दल का होना आवश्यक है लेकिन उसके लिए आप अपने आपका आत्मनिरीक्षण करें।

[श्री नवल किशोर शर्मा]

16 hrs.

इन शब्दो के साथ जहा मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हू वहा मैं कुछ बातो की तरफ ध्यान भी दिलाना चाहता हू । इस अभिभाषण मे कुछ कमिया भी रही हैं । मैं कहना चाहता हू हमने चुनाव मे तीन नारे दिए थे—एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, दूसरा नारा दिया था बेकारी दूर करो, तीसरा नारा दिया था अन्याय हटाओ । इन तीनो बातो के बारे मे, राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसमे स्पष्ट संकेत नही किया गया है । देश मे आज बेकारी का एक बहुत बडा सवाल है । हजारो नही, लाखो नहीं, करोडो लोग बेरोजगार है । उनको एक नयी आशा और एक नया विश्वास बधा था सरकार के कार्यक्रमो से, इंदिरा जी की घोषणाओ से लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे इस तरफ कोई टाइम-बाउड प्रोग्राम की ओर इशारा नही किया गया है । केवल मात्र बजट मे कुछ प्रावधान रखे गए और वह बजट के प्रावधान भी ऐसे रखे गए जिनको स्वय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण के अवसर पर स्वीकार किया था कि कार्यक्रमो के अभाव म यह सारी धनराशि खर्च नही की जा सकी—यह सरकार की असफलता का द्योतक है । आज जब देश मे भयकर बेरोजगारी हो तो सरकार का यह कहना कि कार्यक्रमो के अभाव मे इन कार्यक्रमो को लागू नही किया जा सका—यह अपने आप मे एक खेदजनक स्थिति है ।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हू कि अन्याय मिटाने का नारा भी हमने दिया था । गावो की हालत आप देखें तो उनकी हालत बहुत खराब है । आज गावो मे रहने वालो के लिए पीने का पानी नही है । खेतो के लिए बिजली नही मिलती है । रास्ते और सडको की बात तो क्या करू, रास्ते भी ठीक नही है । दूसरी ओर आप शहरो की हालत देखे कि गगन-चुबी अट्टालिकायें बनती जा रही है । शहर के लोगो के लिए, शहर के उद्योगपतियो के लिए मुफ्त मे सस्ते दामो पर बिजली मिलती है । हर तरह की सुविधा उनको है । हमारे देश की एकोनामी की आधार कृषि है लेकिन उसकी उपेक्षा की जा रही है । आज हालत यह है

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, सदन मे गणपूर्ति नही है ।

सभापति महोदय माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करे । घटी बजाई जा रही है

कोरम हो गया है । माननीय सदस्य मेहरबानी करके एक मिनट म ही अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री नवल किशोर शर्मा गावो की जो हालत है उसकी तरफ ध्यान नही दिया जा रहा है । पचायतराज और कम्युनिटी डेवलपमेंट के जरिए मे जो गावो मे विकास की थोडी बहुत रफ्तार शुरू हुई थी वह भी पिछले पाच-सात साल मे बिल्कुल बन्द हो गई है । आज स्थिति यह है कि गाव जहा के तहा है । तो मेरा निवेदन यह है कि अन्याय मिटाने के लिए, समाज के पिछडे हुए लोगो का ऊचा उठाने के लिए, देश म गरीबो की हालत सुधारने के लिए यह जरूरी है कि ऊच नीच की बात कम की जाये और गावो की तरफ ध्यान दिया जाये । समाज के पिछडे हुए लोगो का और समाज के ऐसे लोगो की जो अब तक पददलित रहे हैं उनके बारे मे भी कोई ठोस कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध म राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण मे कोई सकेत नही किया है । तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि यह सही है कि हमारी उपलब्धिया पिछले साल काफी रही हैं । हमने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अलावा राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी काफी प्रगतिशील कदम उठाए हैं । हमने वह आधारशिला रखी है जिसके जरिए से राष्ट्र समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है । लेकिन इसके बावजूद भी कमिया हैं । हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण मे एक साफ और स्पष्ट निर्देश होता, कोई टाइमबाउंड प्रोग्राम होता लेकिन उसके अभाव मे यह अभिभाषण अधूरा है ।

इन शब्दो के साथ मे इस अभिभाषण का समर्थन करता हू और उम्मीद करता हू कि इस ओर स्पष्ट इगित किया जायेगा जो कमिया मैंने बताई है। धन्यवाद।

SHRI INDULAL YAJNIK (Ahmedabad): I join friends on this side of the House in supporting the Motion of Thanks to the President for the speech that he has delivered I will not review the events of the year that has passed, like our friend Mr A B Vajpayee.

It is necessary, at the moment, to deal with more pressing questions that face us today My predecessor just now had drawn attention to certain lacuna in the President's speech

We have to look at the realities of the situation to which we cannot just close our eyes There is the spiralling increase of the prices of foodgrains and other necessities of life You go to the market and you find that foodgrains are coming into the market and other necessities of life are coming into the market and yet the prices are rising The stocks are there but the prices are rising The only thing here is, it is due to the manipulation of the markets for which the big grain dealers and the big capitalists are responsible. It is they who increase the price, who are not loyal to the people of this country

Take sugar for instance There is a hallaballoo about the rising price of sugar Why was it? It is said that Government has made the mistake in allowing sugar barons to raise the price. They also reduced quantities available for the foodgrain shops and the result is that big commotion all over India is caused Very dirty expressions have been used against the Government by saying that sugar barons have been fleeced to the tune of millions of rupees with a view to getting support for the election fund and that is why they have been given the permission to increase the price of sugar.

श्री हुकम चन्द कछवाय सभापति महोदया, सदन मे कोरम नही है।

MR. CHAIRMAN: The bell is being rung. Now there is quorum. He may continue.

SHRI INDULAL YAJNIK: It is one thing to lay down time-bound programmes, but it is another thing to see that the policies and programmes and laws that have already been adopted are actually carried out in practice

I have recently found the Secretary to the Ministry of Industrial Development, Shri B. B Lal offering on a silver platter the licences or permits for installing whole plants to British capitalists, that is, for installing plants producing all kinds of things in this country This is putting our industrial resolution in the reverse gear Since the time of Jawaharlal Nehru, we have been adopting a policy of swadeshi and of self-reliance as far as possible in the department of industries But here now, we find that a big Secretary is offering any amount of facilities to foreign capitalists to make nonsense of a resolution that has been adopted and has been in operation for all these years

Again, take the case of the Monopoly Commission The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act has been passed And yet what do I find? I find that perhaps more permits and licences have been issued to monopolists after the law was passed than probably was done before the law was passed How does this happen? I would request Government to inquire into this matter I have no doubt that the big secretaries and ICS officers are playing ducks and drakes with the whole course of our policy

Now, because there have been some mistakes committed in giving licences to those who did not deserve them under the new Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, there is an attempt to change the definition of monopoly. I do request Government to appoint a commission or a committee to reconstitute and re-condition the whole structure of the civil service I am sorry to say that the civil service has not been true and loyal friends of the poor and the down-trodden It is they who do run the day-to-day administration of the country It is they who are responsible many times for giving licences and permits to people who do not deserve them Therefore, I do request that more special attention should be given to the new construction and constitution of the civil service. In fact, it is necessary to instil a dose of socialism into the structure of the civil service. The civil servants of tomorrow should know some-

[Shri Indulal Yajnik]

thing about socialism, something about the new economic trends in the world and should be able to help and guide this Government in taking to the new path that has been adopted by this Government and by this House

Then I do believe that we are quite right in adopting the policy of nationalisation. We have nationalised banking and the President has said that we are going to nationalise general insurance by a legislative enactment. But I am sorry to see that nationalisation does not give us revenues. We were told that during the Third Plan period we would get Rs. 400 crores from the profits of nationalised industries We have yet to get this amount : meanwhile, more and more nationalisation is proceeding. I welcome it. I do believe that under socialism, all big instruments of production, distribution and exchange should be brought under the control of society, under the control of Government which represents the society. But I am sorry to see that something is wrong with our nationalised industries. They do not give us revenues.

Again I must confess that I believe that there is something wrong with the top-heavy structure of these industries, something wrong about the large number of sinecures set up to run these industries. There is also this fact that labour is not given a proper deal. Labour co-operation has not been sought and is not available to these industries, with the result that all the big, high hopes raised about nationalisation have not come true

Now I want to refer, however hurriedly, to the rural situation. I recognise that the President is not satisfied with the condition of the Harijans He has laid great stress on land laws. He wants also a ceiling to be imposed on urban and rural property and income. That is all to the good. But may I remind this House that in the opinion of a very great international economist, the socio-economic structure that obtains in the villages today is inimical to the interest of the poor and downtrodden classes ? This economist has told us that probably there is no other country in the whole of south-east Asia that has produced a Gandhi or a Jawaharlal Nehru. And yet how is it that in spite of hundreds of crores of rupees being spent under different Plans, the condition of the villages and the village poor has not been materially affected. He says it is not so much the fault of the Government ; Government has been passing laws ; it has been ear-marking very large amounts of money for the uplift of the downtrodden and the depressed classes, and yet the socio-economic structure that has come down from centuries past remains intact. That makes absolute nonsense of all the good designs and programmes formulated by the Government.

Therefore, I believe something has to be done in order to change or reform or materially reconstruct the socio-economic structure. Since times immemorial, Patels and Mukhis and now Panchayat Presidents rule over the destinies of the villages, and they naturally reap the harvest. They get the best benefits out of all the money that is spent in the villages. I would, therefore, be very glad, and I am very glad indeed to see, that the President in his concluding remarks has called for a big fight against poverty and against unemployment. It is a great gospel that has come to us -- *Garibi Hatao*—and I am glad to see that the United Nations also has thought according to latest reports of observing an international year for the eradication of poverty. But may I emphasise that this poverty and unemployment cannot be eradicated merely by official programmes and policies and grants and subventions that can be given by Government ? No doubt the Government has a big part to play. Indira Gandhi has been sweeping this country with her slogan of eradication of poverty, and that creates a very good atmosphere for the development of all programmes and all efforts for the eradication of poverty.

But I do feel that the people who are affected by poverty and unemployment have to be awakened. Their bodies and minds have to be vitalised They must be organised into kisan sabhas, workers' Unions, Artisans' Unions and people's unions and people's committees which should undertake spontaneous efforts, and spontaneous activities in order to create a new atmosphere in the villages and in order to break down, bit by bit, the old socio-economic structure which has been manipulated by the top-rich in the villages for their own benefit.

Therefore, I do feel that it should not be the duty of Government alone to eradicate poverty. Let the Government clearly and emphatically say that they alone can do a good bit in order to eradicate poverty but

their hands must be strengthened by the voluntary efforts of millions of men and women in the countryside who must take up cleaning the villages, building little houses, developing organic manures, cleaning wells and ponds and do many other things with the help and support of the Government, whether it is the Central Government or the State Governments.

I would, therefore, request that a word, a call should go out to the unemployed millions in the land to organise themselves to do a bit of voluntary effort also in order to rehabilitate themselves, in order to reconstitute their lives, in order to activise their minds and bodies and in order to create a feeling of solidarity, equality, fraternity and liberty in the rural countryside. If these common people do put their best efforts, then, in that case, I think all the efforts of municipalities, Governments, panchayats and co-operative societies will bear rich fruit with the co-operation of the millions who are affected by this slogan, eradication of poverty

MR. CHAIRMAN : As Dr. Karni Singh is the only Member from his Group he can take all the time allotted to his Group.

DR. KARNI SINGH (Bikaner) : Madam Chairman, I feel it my duty to begin my speech by congratulating our brave jawans and the hon. Prime Minister and the Defence Minister for the wonderful way in which the Indo-Pakistan war was handled. It gives us great confidence to know that the Indian Armed Forces, including the Navy and the Air Force, have such fine calibre of fighting men that in the shortest possible time of fourteen days, we were able to liberate Bangla Desh after unprovoked aggression was committed on our own borders.

I have written to the hon. Prime Minister myself and I feel I must publicly confess today, about the remarkable way in which she handled the Bangla Desh affair ; not only that. I consider to be a master-stroke of diplomacy the fact that the Government ordered the cessation of hostilities immediately after the war in Bangla Desh was over and Bangla Desh was liberated. It was a master stroke that has given India great prestige throughout the world. The Prime Minister and her colleagues, the hon, Defence Minister sitting here, deserve every word of praise from every body, including Opposition and the country as a whole.

Sometime ago, I think it goes back to 1952 or 1953, when I was a very young Member of the House ; I had raised the point in the Select Committee on Estate Duty of which I was then a Member, that the Armed Forces and police forces killed in action serving their country should be exempted from estate duty. I do not know exactly what year it was, but the Armed Forces were finally exempted and later on the police forces were also exempted. It was a virtually lonely battle I waged to achieve this. There may be yet some lacuna in the law where by the Home Guards, the NCC and other types of people who may not strictly come in the category of Armed Forces or police forces, might be left out. They have fought very well on the borders also.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : They are covered.

DR. KARNI SINGH : I had written to the Government during the war about this and I am very happy to know that they are covered, because I feel a sense of responsibility having sponsored these motions on the subject since 1952

The elections for the State Assemblies proved to be a calamity for the Opposition. As an opposition Member myself, although I am an independent and belong to no party, I can say one thing that these elections, as far as I was able to see, were fought fairly and freely. There was no Government interference in the State of Rajasthan—although I would have been glad to have seen an opposition Government come to power nevertheless—I must congratulate my friend Mr. Barkatulla Khan, a man I have admired very much, who saw to it that the Administration did not interfere with the elections. In 1971 during the mid-term poll we had the opposite experience, but this time I feel that the Central Government and the State Government Chief Ministers deserve every word of praise.

I have been for many years an independent and had the temerity to speak to my friends on the Opposition benches to unite. Inspite of all the efforts made by people throughout the country to create a strong and

[Dr. Karni Singh]

healthy united opposition, we have failed. So much so, in the Fifth General elections this year for State Assemblies, the major opposition parties fought against each other. I feel it is no use for us in the opposition merely to blame the Congress for all the ills in the country. We in the opposition have also failed to realise that the country needs a powerful opposition, that the people need an alternative to vote for. I am quite convinced that the people in my State of Rajasthan gave the Congress their mandate because the opposition parties were fighting among themselves. The Jan Sangh and the Swatantra party, for instance, fought 13 of 16 seats in one district in Rajasthan alone. This is the unfortunate state of affairs, If the opposition leadership actually feels that democracy in the country can be saved by a powerful opposition and the balance of power being kept between the ruling party and the democratic opposition, then their responsibility, *uttar dayitva* to the people is very much there, If this situation continues as it is, I would not be surprised if in the next elections you may find no opposition members here; barring the communist members. I think the time has come when all the opposition parties will have to do a little bit of soul-searching and they will have to make for the greater, good sacrifice.

SHRI R. S. PANDEY: We shall help you to come.

SHRI KARNI SINGH: I have done 20 years; my time is over.

There is one thing which I feel as an independent. The opposition today will have to merge all their fancy names like X, Y, Z party have to go. In the interests of the country, in the interests of democracy, the opposition will have to merge into one new party, a democratic socialist party, or whatever it may be called, e.g., a party that would through its strength see that the Government is kept on its toes and that good Government is there in the country. Otherwise, whatever happens to the country, the opposition will have to share the blame as well

About a year ago, I brought some Private Members' Bills before Parliament but they were defeated. The first sought to give children under 14 free and compulsory education and for old age pension, and the second one was for unemployment relief. I feel that with the President's Address laying so much emphasis on poverty and its eradication, these measures should be revived this time by the Government itself. It is no use opposition Members bringing these socialistic measures and their being defeated. It is the Government's responsibility to see that every child, according to the Directive Principles of the Consititution, gets free education, that people who cannot be employed are given some kind of dole or compensation and that old people are provided for in a socialistic State.

Speaking about the industrial backwardness in certain parts of India, and I will refer here again to my own State, some of us who are elected from the desert regions of Rajasthan find that ever since independence there has been no major industrialisation in these backward areas. For instance, you know that about 15 years ago a committee was set up to visit Rajasthan and choose a site for setting up a fertiliser factory. In Bikaner Division, either in Ganganagar or Bikaner District, it was recommended by Mr. B. C. Mukerjee, if I recollect all right, he chose that site because the raw materials including coal, gypsum, water, *etc.*, were readily available. I would like to make an appeal to the Government that when we are trying to develop a country, backward regions will have to be given higher priority. Industrialisation has to take place even if you lose on it. After all, State enterprises can afford to lose, and so many of them are already losing. But, after the integration of the former States, it is necessary for the Government to be able to prove to the people that they have in fact done something to raise their standard of living. If year after year representatives of these desert regions keep on pressing their case and Government turns a deaf ear to them, you can understand that the aspirations of the people are not going to be very high. And now that the people have given a massive mandate to the Congress Party, I think that the Government should pay a little more attention to these under-developed areas.

There have been requests for connection of certain areas by Railways. For instance, we have been raising for years the question of

the stopping of a train at Parihara in Rajasthan. We wish to make today a request for a rail link from Ratangarh to Jodhpur via Devana. Perhaps you know in the former Bikaner State, my grandfather was responsible for 1,000 miles of railways being built. Since independence I think we have built about six miles. I have said that there are many areas in these regions which can be developed by new railways Perhaps the Government would like to consider linking Taranagar in Rajasthan with Bidasar and some other places in the desert, so that we can have modern amenities and developments can take place.

Another point which does not receive the priority that is necessary is tubewells in the desert Sufficient funds have been provided by Government for digging big tubewells, but in the villages where they have been dug, the machine is out of order. The machine has been sent for repairs and has not come back for one year, and there is no water supply to villagers Government has already invested large sums in the tubewells and the people have also contributed to it. If these tubewells are out of order, there must be some method to see that their repairs can be taken up expeditiously and that red-tape does not come in the way.

Similarly take rural electrification. I know many villages where people have actually paid money in advance as their contribution and yet the matter has been hanging fire for years and rural electrification is stultified. In this situation, I feel Government can perhaps issue orders to the State Governments and see that a suitable machinery is set up so that these matters can be dealt with expeditiously and the poor villagers not denied their rightful due of progress.

Regarding Rajasthan Canal, which we have been demanding for a long time that the Centre should take over this national project this is perhaps one of the most prestigious and biggest projects in the world; particularly the Rajasthan Canal Lift Channel which is perhaps one of the biggest projects of its kind anywhere in the world, counting Russia and USA and certainly it should get the highest priority. Every second year we come to the Centre for help for famine relief. If we have enough irrigation, the need for the Centre to dole out money every other year for famine relief would be reduced and there would be agriculture everywhere. If you visit Ganganagar, you will see that that once desert region has the highest number of tractors in any district in the whole of India. That was a desert at one time. All we need is water and I request that the Government may kindly give this matter their earnest attention.

One point which has been exercising the minds of very hon. member here is rising prices and black money. I would like, as an Independent, to say something about black money. Nobody wants to see black money in the country. I am sure the ministers opposite are trying their best to eradicate it. But when your taxation structure and your laws are so unrealistic, a certain point is reached when a citizen has no other way to survive except through black money. I would like to say this because I have seen in the last five elections that I fought that no election is fought without the use of black money. Why? Because your unrealistic law says that no Assembly election can be fought for more than Rs. 12,000 and no parliamentary election can be fought for more than Rs. 35,000, resulting in—I do not know how many; God knows—hundreds of us in this august House having to file affidavits which we know are not correct. It is an unrealistic law which makes you sign a wrong election return. In the desert, to fight a parliamentary election, one spends more than Rs. 35,000 on petrol alone, at Rs. 7 a gallon. If the Government makes laws that cannot be followed, the result is, use of black money. The ruling party must be first set the example not of use black money in politics.

Take taxation. The Wanchoo Report obviously has given to the people of the country an idea as to how high the taxation slabs are. As a result of that, people are resorting to use of black money. If I remember aright, Prof. Kaldor said that the total incidence of direct taxation should not exceed 60 per cent. In India, it has reached a stage of 200 per cent, not 60. I say this from my own experience, because today I am paying 200 per cent indirect tax on may income. There are not many people who are born as semi-gods or saints on this earth. Every man has desire to survive. No man minds paying taxes provided they are within his paying power. But with the generations changing,

[Dr. Karni Singh]

where tomorrow the children will no longer feel responsibility for looking after their aged parents, it is incumbent on the Government to see that as a citizen grows older, he can look after himself and not be thrown into the streets when he is for old to care. We have no old age insurance also. But the taxation levels as they are will put any man, if he is honest in paying his taxes, within a span of five years on the street. In this situation, if the Government goes on bringing in unrealistic laws, and absurdly confiscatory taxes the result must be use of black money. Therefore, I submit to the Government that the taxation slabs should be so realistic that they are within the paying capacity of the people. If you say socialism, I accept it. If you say, there is inequality of wealth, I accept it. In fact, for the last ten years, I have been saying, let them have a capital levy and take away 50 per cent of what the rich people possess in one go, let us then remove the wealth tax and take the income-tax upto 80% or so in the highest bracket. Let them leave a man with a reasonable amount to live on. These are matters which I feel Government will have to consider more so now, as the Wanchoo Committee Report supports what I am trying to say today. Even the Constitution says a man is "entitled to the fruits of his labour".

The question of urban property ceiling has created a panic throughout the country. Here again, I feel we are working more in fashion. We are not worried about the realities of the situation. A ceiling of Rs. 5 lakhs, Government say, is going to be imposed throughout the country. Jansangh may say that it should be Rs. 2 lakhs and some other party may say that it should be Rs. 1 lakh ; this competition is rediculous. But, has anybody tried to think of what is the value of property in a large city like Delhi, Bombay or Calcutta ? Recently I was trying to get a flat in Bombay city and I was to told that a flat would cost Rs. 5½ lakhs, so much under the table and so much above the table. Because, everybody knows that if you pay legally Rs. 5½ lakhs for a flat that would be confiscated under the urban property ceiling. You may ask : why do you want to live in Malabar Hill? Then I will say you may very well pass a law that Malabar Hill area should be used by foreigners only to live and not by Indians. Now people like us are going to lose our homes in the cities if the urban property ceiling of Rs. 5 lakhs is applied. When that situation comes, at least nobody can have a home in Delhi or Bombay ; you cannot have even a flat. And if you are going to allow payment for it partly under the table then you are only encouraging black money.

I can understand the desire of the government to bring in an urban property ceiling but surely urban property ceiling should be realistic. It should bear in mind the rising prices, the cost of materials and so on and so fourth.

So much has been said about the rural sector and it is mentioned that Government have brought in a ceiling on rural and agricultural land. Well, I can understand it, because there is limited land in India due to over population and limited irrigation potental in the country. But I would like to ask just one question. What is the shortage of space upwards, in the skyscrapers ? I am sure that in any part of Delhi, in the outer areas you can build enough skyscrapers to house all the people of Delhi. You can have 30 or 40 floors with lifts and other facilities and it would not be difficult to provide accommodation for the working classes. After all, it is a socialistic state. Why should the socialistic state not be able to give a house to every worker, be it on the 40th or the 100th floor ? What is the difficulty in building skyscrapers flats and giving them to the workers ? Why take away people's houses they have been living in for generation ?

You know that for every human being no matter where he lives, be it in India, America or somewhere else, it is the primary urge to own a house. But in this country you want to dispossess the people of their homes and then you want to say that this is being done for socialism. Who is going to benefit by this ? When you impose this ceiling anybody who wants to live in the middle of Delhi city will not be able to have a house because even a flat will cost more than Rs. 5 lakhs if correctly assessed and there is corruption that follows arbitrary valuation.

So, I would request the government to

bear in mind one important point. A house owned by an individual for his residence is one thing and a whole line of buildings owned by a person for business purposes is a different story. For instance, if Mr X owns 50 blocks of building in Chowringhee or Cannaught place that is one story and if Mr. Y owns one flat worth Rs. 5½ lakhs for his own stay, that is another story. You cannot equate residential buildings used for making money with home used for personal living by the family more so if they have lived there for a large number of years.

Then I come to the retrenched staff of the former princes. I have said this many times before, and I am going to say it again. The Twentysixth Amendment to the Constitution abolishes the privy purse. Over one lakh, perhaps two lakhs, people are going to be thrown out of jobs, or some of them have already been thrown out of jobs. Now, surely a government which claims to be a socialist government, and a socialist state at that, will try to find some ways of employing these people. Some of them are beyond the stage of employment. For them you have to provide old age insurance. There are old women who cannot work any more. For God's sake, on humanitarian grounds you owe a certain duty to them. You have abolished the princely system ; very good. But you cannot wash your hands off these hundreds of thousands of people who were drawing their sustenance from this system. I feel that the government will have to make special provision for employing these people.

Turning to Sports, Olympics are nearing fast. I feel that our hockey crown is very much in danger. Those who are sportsmen know really how much prestige is attached to a country winning a gold medal in the Olympics. I feel that unless we realise the need for the selection of the team and their training facilities and take necessary steps urgently in that direction, we are going to lose the hockey crown in Munich which I say with much regret.

I have seen India win and lose the hockey crown in the Olympics in the past and I would hate to see Pakistan or any other country beat us once again. Therefore, I would request that the training of these teams and their selection should be done by the Government at the topmost level.

There is another thing which was brought to the attention of Government by me in a resolution once. That was about South Africa's participation and India keeping out because of that. I had mentioned that even the Soviet Union, which did not believe in apartheid, was taking part when South Africa participated. Yet, for the last two years the golf and shooting teams have been stopped from participating in World meets because South Africa was going to take part. I am not against this policy generally but I would only like to ask the Government how much help or sympathy we got from the African countries in the recent Indo-Pakistan war. If their heart does not bleed for us, I do not see why we should go out of our way even to spoil the future of our sportsmen. After all, sports and politics are separate. I would request the Government once again that they should not bar Indian teams from participating where South Africa participates. We should try and throw South Africa out, but if we cannot, let sportsmen fight and defeat South Africa as we have done in shooting practically every time. You are going to create a dilemma for yourself because in the Davis Cup in which India has done so well, South Africa has been permitted. You cannot discriminate between tennis and other sport. I wish, Government will go into this matter seriously. I had raised a discussion on the floor of the House on the Sports Policy and I repeat this point.

While concluding I would like to say that the slogan of *garibi hatao* is very important but it should not remain a slogan. We have to act in this thought. I find that, as time goes on, *garibi hatao* is being forgotten and *amiri hatao* is, coming in. *Amiri hatao* is a negative approach. Because you have failed to *hatao garibi*, therefore *hatao* all the *amirs* so that there are no *amirs* and all are *garibs*. I feel, what we should try is to raise the standard of living of our poor people. Give them a better standard of living and get more amenities of life for them. That will be a positive line, level up should be our motto.

With that I will conclude only with this hope and prayer to Almighty that this horrible corruption, that we are coming to grips with today in all administrative sectors, this poverty and these rising prices are problems to fight which all of us from all sections of this House should put our shoulders together and try to eliminate them.

SHRI RAJA KULKARNI (Bombay-North-East): Mr. Chairman, I join the Mover in his motion of Thanks to the President. It is quite natural for Shri Vajpayee to apprehend fear about the future of democracy, because Shri Vajpayee's concept of democracy is not that of the people. The people not only in this country but in the whole world are acclaiming the Prime Minister and are saying that the working of democracy in India is quite safe and dynamic and will be helpful not only for the consolidation of political democracy and the working of parliamentary institutions but that democracy has now become dynamic and a powerful instrument in this country for helping the Government in their policy of social and political amelioration

Shri Vajpayee now apprehends that fascism might come because too much power has been given. It is not Shri Vajpayee who has given the power to Shrimati Indira Gandhi; it is the people who have given the power. Through these elections and the massive mandate, which the people have given to the Congress Party, they have done a great service to the working of democracy. Democracy now is completely consolidated and is now ready to take off for the social and economic transformation which is the need of the hour. The country is impatient ....(*Interruption*)

श्री हुकम चन्द कछवाय सभापति महोदय, मै व्यवस्था चाहता हू, सदन मे गणपूर्ति नही है ।

MR CHAIRMAN: The bell is being rung ...now there is quorum The hon Member may continue his speech

SHRI RAJA KULKARNI: The people of this country during the last one year have brought political stability, both in the mid-term elections of 1971 and in the recent elections to State Assemblies This political stability is a thing which must be appreciated. If the Opposition parties are routed, if they are uprooted, it is because of their mistakes. If they have lost the social base and mass moorings, it is not the fault of the ruling party. In the recent past, they were working and making a lot of efforts to work in a united front to create a big Opposition in the working of our parliamentary democracy. But they failed. The period of last 5 or 6 years is a history of failures of the Opposition parties. Now, for the failure of the Opposition parties, both of the right and the left variety, it is not the ruling party which should be blamed. It is not the fault of the ruling party if it gets a massive mandate. It is a lesson to the Opposition parties as to how they can work in a parliamentary democracy. I hope, they will take a lesson and, instead of trying to create anti-Congressism as a philosophy, they will take more interest in developing their own strength on the basis of their work and their contacts with the masses

Now, with the political stability that has come about the country has laid down the tasks in the President's Address The task is of the social and economic change It is not the philosophy that has been laid down. The philosophy of democratic socialism, the evolution of the democratic society, is already there in the Constitution. It is not the philosopy of one party as such. It is the nation's philosophy

We are in the midst of revolutionary changes Actually, we are in the process of change. The task is not of searching a philosophy. The task is of accelerating the pace of social and economic change, the task is of finding an appropriate pattern. It is to find out what is the pattern and how to accelerate the pace. So, it is the pace and the pattern that matters Socialism is not a question of philosophical thinking. It is a question of finding a democratic and socialist pattern which will bring about a successful change and take this process to its logical end.

When the people give their massive mandate to the leadership of Shrimati Indira Gandhi and her programmes, the people know her programmes and the people are aware that their problems are still not over. They know that it is Shrimati Indira Gandhi and the ruling party that alone can help them in making this process a complete change in their favour. They know that the social and economic revolution can take place only under the leadership of Shrimati Indira Gandhi. It is the mood of the confidence that matters; it is the creation of this mood of confidence that is very improtant in completing this process of change. Today socialism is no longer an academic thing to us; socialism has been taken out of the books of academi-

cians, out of the lectures of professors. Today, in our country, the process of change has come. Socialism has become actually a product of the masses themselves. It is they who are striving to build this process of change. That is socialism. Now a programme has been given ; a time bound programme has been given ; a direction has been given. Democratic socialism has been put as an objective. There is an objective, there is a direction, laid down by the programme. And with the leadership that has now been created and with the efforts and strivings of the people, this process of change is now to be completed at the earliest.

Today what is the assessment of the victory of Congress? It has liberated, released, the creative abilities of the common man in this country. And that is the essence of socialist victory of the recent elections. These creative abilities of the common man are now, after the emergence of Bangla Desh, to be mobilised and are to be made more effective through the programme that we have got. It is, therefore, this process that has to be done now. It is the Opposition parties' task to help in accelerating the pace and evolving appropriate pattern.

Today Shrimati Indira Gandhi has given us what Gandhiji gave in 1920 when he assumed the political leadership of the freedom struggle. It was Shrimati Indira Gandhi who, at the end of 1969-70, brought this objective of economic growth with social justice. In the 1950s and 1960s, emphasis was laid on economic growth, and it was assumed that social justice, social progress, would be a by product of economic growth. It is Shrimati Indira Gandhi, it is the Congress under her leadership, who has brought these two processes together. It is this that made the the socialist movement in this country, the people's movement in the country; it is an electrified effect ; it brought life into the people, and they saw the liberation at the earliest under the leadership of Shrimati Indira Gandhi.

In 1920 there was a controversy before Gandhiji assumed leadership whether primacy should be given to political reform or social reform. Gandhiji brought both of them together. It was a synthesis of the two that he brought about. Today the programme of social justice, the programme of social progress and the programme of economic development have been brought together in a synthesis by Shrimati Indira Gandhi, and a time-bound programme has been given. We have now to help and cooperate in accelerating this pace. It may be that, in giving this programme of Arthik Swaraj, self-reliance, there may be some programme given to each section of the people. For the labour, we have been told about moratorium on strike. We in the trade union movement have been appealing to the people that we stand for economic growth with social justice, but at the same time we want economic production not by legislative sanctions on strike, not by any non-legislative sanctions on strike. Strike is a fundamental thing. Let conditions be created whereby people in the factories feel that social justice is given to them. Let the workers in the factories feel that new laws are evolved whereby they get justice immediately to their long-standing demands, to their fair demands and a prompt settlement is arrived at for their disputes. If a new code of settlement of labour disputes is evolved, then there would not be any necessity for bringing forward any such legislation or non-legislative sanctions like moratorium.

17 hrs.

Therefore, I would request all, whether they belong to this section or that section, this Party or that Party, that the time has come—there is no question of majority or minority Party—when all people should unite, as we united in the recent struggle for the liberation of Bangla Desh. Here is the moment when, for the success of socialism, all sections of the people should unite as one man under the leadership of Shrimati Indira Gandhi and accelerate the process of change with the pattern of the programme she has given.

With these observations, I support the Motion of Thanks.

MR. CHAIRMAN : Shri S. A. Shamim—absent.

Shri Baladhandayutham.

SHRI K. BALADHANDAYUTHAM (Coimbatore) : Madam Chairman, I am sorry I have to submit that the Address by the President of India to Parliament is an

[Shri K. Baladhandayutham]
anti-climax coming in the background of the glorious victory in the war and an equally glorious victory in the election battle.

In the war, we fought against the imperialist forces and their allies from outside and defeated them, and in the election battle the victory was won against the forces of imperialism inside this country. But, coming in the wake of such glorious victories, the policy statement of the Government embodied in the Address by the President of India is a shocking contradiction, and it appears that the leadership of the Government is frightened by the new prospects and responsibilities.

The President's Address ends with a high note of war against poverty. By that, I presume that the challenge of poverty is going to be taken up on a war footing. When you talk about war, you always name the enemy You identify the enemy. Poverty is not natural. India is a rich country. India is rich in its man-power. India is rich in talents Still, the people are poor. So, if you talk about war against poverty, what is the system that generates this poverty, what are the forces that cause this poverty, or what is the obstacle for the eradication of this poverty ? The Government which had the guts to identify the enemy in the war and deal with him ruthlessly has not got the guts to identify and name the forces and classes that generate poverty in this country.

17.04 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

Here is an attempt, and I would forewarn the Government that this attempt would end in failure. Here is a serious attempt being made to change the entire condition of life to eradicate poverty within the framework of a system which generates poverty. The President's Address does not address itself to the abolition of the socio-economic system, the capitalist system and without trying to abolish the system, they make demagogic promises and claims of abolishing poverty. It is but natural, because a Government which is not able to recognise the role of the Indo-Soviet pact in dealing such a terrible blow against the enemies of this country cannot also realise its role after the war. We should recall the conditions when the danger of an attack from Nixon-Chou-Yahya Khan axis against this country was there, and we can see the actual use of this pact and the role this pact has played.

I am surprised to find that the role of that pact, the impact of that pact, has not only been missed in the President's Address, but it is missed everywhere.

I was shocked to see a documentary produced by the India Government on Bangladesh which tells you everything. There is not a mention, not even an indication, that there was an Indo-Soviet pact which played a very big role in the liberation of Bangladesh, for holding the Chinese Forces and the Seventh Fleet of the USA at bay. Apart from its role during the war, it has a role to play in the future also. When you say about self-reliance you do not talk about who is your friend and who is your enemy. If you mean by self-reliance, self-sufficiency, it is never going to be attained by any country

When we talk about self-reliance we mean that we are not subordinate to an imperialist country and a country which wants to exploit this country, but that we are willing to take help from countries which are friendly and which do not come to exploit us, the friendship with such countries not only strengthens you but helps them also. This is a friendship on the basis of equality, for the betterment of the economy Here is a Treaty for 20 years which not only stands for peace, but helps us in the economic advancement of the country. This role has been underplayed in the President's Address, not unwittingly, but deliberately.

We talk about abolishing poverty on a war footing. If you want to name the enemies, during the war, every child knew who was a friend and who was an enemy of the country. They knew American imperialism as the enemy of the country and Soviet Union as a friend of this country. When you talk about *arthik swaraj* you do not mention about the role of America in the past or its plans in the future with regard to the exploitation of this country.

An image has been built up in this country of the Prime Minister because of the nationalisation of banks followed by some other steps. It is really surprising that the

Prime Minister is out to abolish poverty in this country without dealing first with that system which makes this rich country so poor, without first changing the socio-economic structure built by the British, which is being continued. We should have dealt first with foreign investment and foreign capital in this country which is growing, and the amount we receive is not commensurate with the independent development of the Indian economy. Have we ever thought of nationalising important foreign firms? Foreign oil is a field where the nationalisation step is indispensable for the development of Indian oil for the preservation of our security and for the economic development of the country But we have not nationalised the foreign oil trade Yet, all the time, we are talking of the black money. Black money is not only hiding and circulating in this country It is circulating abroad also. Now is there even the idea or suggestion of nationalisation of foreign banks?

With regard to foreign capital, they are given complete freedom, and what is more, today, we see the extraordinary phenomenon of getting planes as such from Britain and the Netherlands, scrap which was dismantled there because it could not run there is being brought here in the name of Arthik Swaraj.

Coming now to the next enemy, namely monopoly, what nonsense is it to talk about controlling monopoly: 40 per cent of investible capital is with them and yet Government say that they would not give them licence. Where is the capital to invest? Then, what happens? When Government take the unrealistic position of trying to control something which cannot be controlled, but which can only be eliminated or abolished or nationalised, what happens? They have given them 54 new licences When the hue and cry comes that 54 new licences have been given, they say that it cannot be helped. So, I submit that this question of monopoly cannot be dealt with in the manner that Government are doing today.

I am taking this question up seriously, because it is not merely in the Address that monopoly has been forgotten, but our Prime Minister has now found new virtues in the monopoly houses. In her address to the FICCI, our Prime Minister has now found new talents in the monopoly houses, and she has appealed to them to co-operate; she wants their talents and the people's money for joint enterprises. This new slogan of joint enterprises has come after this glorious war, after this glorious victory in the elections. The people wanted change, and the Government promised them change, but here they are only changing from control of monopoly to co-operation with monopoly and to finding virtues in monopoly.

The third enemy about whom they were talking when they were fighting the Syndicate and when they were fighting the British is landlordism. How casually the President's Address tries to deal with it. I was shocked to read a commendation of the reduction of ceilings in Tamil Nadu. What happened in Tamil-Nadu? The Central Government have not even gone into the question of what sort of legislation has been passed with regard to land ceilings in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, they have reduced the ceiling from 30 acres per individual in a family to 15 acres, but at the same time permitted partition of land even among minors.

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : What is the harm if minors are given?

SHRI K. BALADHANDAYUTHAM : I shall illustrate my point with an example and show that the family then retains a larger holding.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : In Madhya Pradesh, land was transferred even to a dog.

SHRI K. BALADHANDAYUTHAM ; A friend of mine came to me once seeking my advice regarding the Tamil Nadu legislation. He had gone to the High Court against the land ceiling Act of Kamaraj, that is, which imposed a ceiling of 30 standard acres. Having gone to the court,—the case is going on—he was asked to surrender about 400 acres of land, based on the calculation under the old ceiling law. After the new law, he finds that he can buy 300 acres more. He wanted to know how he could withdraw the case from the High Court. There is one provision in the old law which does not allow him to withdraw the case so that it could come under the new Act, So, he has to suffer under the old Act, because the whole process had been gone through at that time. He is sorry that

[Shri K. Baladhandayutham]
the whole thing was closed before the new Act came into force.

If you peruse the law, you would find that it is worse than even the old law, because it does not give one more acre to the poor. If you talk about land distribution and taking over of land in excess of the ceiling, then I submit that the Tamil Nadu land reform law is a failure. And yet, here is the President's Address which hails it and commends it as an example for the future State Governments that are coming into being and that are to follow the example of Tamil Nadu.

We no doubt hail some of the Acts which they have brought in pursuance of the Industries Development and Regulation Act, for instance, the Act under which they can take over closed units. But I would give you one instance in Tamil Nadu where nothing has happened so far. There is the case of the Balram Verma textile mills, which was closed down three years back. The investigation was completed two years before, and yet that factory has not been opened even today. The Government are not taking it over. Whenever we ask them, they say 'We are taking it over'. Three days ago I was told by the Minister in reply to my question that it is not being taken over. Why ? Because the owners do not want it to be taken over. They approached the Finance department and were able to get men inside that Department to send the proposal back saying : 'The investigation is out of date. It was done some years back. So you must do fresh investigation'. Here is a law which enables you to take over closed factories, but it can be scuttled by an official of the Finance Department if he has got links with the owners.

In Tamil Nadu, the entire body of textile workers have gone on strike for a month. Still the mills are not taken over. Still four or five of the textile mills remain closed. There is fall in production, factories are closing down and the existing factories are looting the workers. You talk of production. Next you talk of a moratorium on strike. The whole emphasis in the Address seems to be that the workers must work, you must spueeze the workers and the talent of the monopolists and the ability of the landlords must all be pooled together for building the new society. This is sheer moonshine. You are not having a perspective ; you are not launching on a new path. Now the Prime Minister wants to lay a new path in collaboration with monopolists, with the members of the FICCI.

How blind can the Government be to the Indian realities can be seen on the question of Centre-State relations. I must bring to the notice of the House that the slogan raised in Tamil Nadu is not that simple. The slogan is very subtle. They say : Mujibur Rahman fought against Urdu , we fought against Hindi Majibur Rahaman demanded provincial autonomy , we are demanding provincial autonomy. Mujibur Rahman got Bangla Desh ; as to that will happen to us, we leave it to you to understand.

There is not only a Mujibur Rahman in Tamil Nadu in the person of Shri Karunanidhi ; there is also a Mujibur Rahaman in Ceylon in the person of Shri Shelvanayakam These Mujibur Rahamans are raising this slogan because they know that the Central Government are blind to this question of Centre-State relationship.

You are now talking of overdrafts. Have you gone into the question of why overdrafts are there ? Have you gone into the question whether there have been financial irregularities and bad habits with State Governments, or the State Governments are really hard put to it to find the money necessary for ameliorative and developmental activities in the States ? You have not done it. You are supremely complacent because you have got an election victory , you are complacent because from Delhi you are able to run the States today. But may I warn you that those people who raise the slogan of Mujibur Rahman inside are not alone ; they are being backed up by forces from out side. Nixon and Chou En-lai met in Peking and discussed the question of Kashmir. When they discussed the question of self-determination for Kashmir, they wanted a diversion in the south also. They are behind this diversionary slogan from the south. You are not going to deal with it with arms ? You can deal with an outside power by resort to arms. But you cannot solve this problem with arms. It has to be solved by seeing that with regard to the powers and financial resources and the help given from the Centre, the Centre revises its

blind attitude. The Centre should go into the question, examine it whether it should not give more powers, a lot more finance to the States This is a very difficult question, a ticklish question, a complicated question. If necessary, the Centre must come forward with amendments to the Constitution on this question ; otherwise, it will be feeding secessionist movements in this country.

Coming to other things, you talk about a moratorium on strikes But when it comes to a question of participation by workers in the management of public undertakings, I find the public undertakings are the worst managements worse than even private sector managements. This is because they are being manned by bureaucrats Apart from that, the Centre also intervenes. Here are the nationalised banks. Glorious. But when they constitute boards, see how unfair is the allotment. They give in the name of representation for farmers, workers and ordinary people 9 seats for INTUC. Three seats were given for the HMS and only two seats for the AITUC. You talk about participation and representation for the workers in the Public undertakings, and you fill up those places with your own men. It is not going to harm others, but it is going to harm yourself because you are going to understand the feeling and the needs of the people if you go on in this undemocratic way.

You went to the elections on the question of the privy purse of princes and their privileges. Again now you went to the polls saying "we have abolished it. But what about the privileges of the ICS cadre ? In the Rajva Sabha, a non-official Bill was brought, and my impression was that the Congress was committed to the abolition of these privileges of the ICS cadre. Why did you not take it up and why is there no mention of any Bill in the President's Address ? You are bringing so many Bills, but you have not thought about the ICS. So long as the privileged class of the ICS is there, bureaucracy has become the main obstacle to the implementation of even the little that you plan here in this Parliament.

There was a talk about the diffusion of ownership of monopoly newspaper houses, of separating them from industrial magnates. But what has happened to that Bill ? Why is there no mention of it in the President's Address ? Why have you got cold feet ? It should have been there long before. If you are not going to control this means, this medium of propaganda which is in the hands of the monopoly houses, how are you going to control them and how are you going to restrain them and how are you going to regularise them ? It is impossible. So, it is not accidental that that Bill is not mentioned as one of the Bills that are coming before this House in this session.

Further, even the little that is done is being scuttled because of the present posture of the Indian Government. There was an uproar in the Rajya Sabha over the devaluation leakage by the United Commercial Bank. Proceedings were set in motion ; M. P. Jha and some others were arrested. But having done that, for propaganda purposes, the whole case is being sabotaged, and you are not trying to get at the truth. You are not trying to deal with the culprits. What is more, if you talk about enemy, if you talk about resources, the question of black money must be seriously before you.

MR. CHAIRMAN : Your time is up.

SHRI K. BALADHANDAYUTHAM : You are not lenient; you were lenient to others. If the Chairman wants me to wind up, I will finish.

MR CHAIRMAN : You may have one or two minutes more. I am lenient to you too

SHRI K BALADHANDAYUTHAM : I protest against this discriminatory observance of time.

SOME HON. MEMBERS : You may continue.

MR. CRAIRMAN : You have been given 23 minutes.

SHRI K. BALADHANDAYUTHAM : I am sitting under protest.

MR. CHAIRMAN : Protest is a very easy thing. (*Interruption*)

AN HON. MEMBER : He can continue.

MR. CHAIRMAN : He does not want . *(Interruption)*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : Sir, the word "discriminatory" was not proper, particularly when the hon. Member had already 23 minutes. We on this side of the House also requested you to let him continue and finish it. We did not say no to it, and the Chairman also did not say no. I hope he will kindly appreciate the position and withdraw his word discriminatory".

SHRI K. BALADHANDAYUTHAM . I have been sitting here and observing the way the time has been allowed. Members who are asked to finish were given five, ten or twelve minutes more after their time was over, and I have been asked to sit down. *(Interruption)* So, in observing the same rule, there is discrimination. I stand by it and I refuse to withdraw it. I am prepared to undergo any consequence as a result of asserting that discrimination is there

SHRI RAJ BAHADUR : Why should you lose your temper for nothing ? We did not offend you at all. You are offending us.

MR. CHAIRMAN : Order please Shri Vidya Dhar Bajpai not here. Shri Md. Jamilurrahman.

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मुअज्जज चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट मे मेरी जान पहचान और मेरी जिन्दगी बहुत थोडी और छोटी है । इसलिए मैंने सोचा था कि आनरेबल मैम्बर्ज के तजुर्बे का फायदा उठाते हुए सदर जम्हूरिया के खिताब पर ऐसे सबजैक्ट्स पर चर्चा करूंगा जिनके ऊपर ध्यान देना हमारी कौमी जिन्दगी की बेहतरी के लिये, मेरे ख्याल में जरूरी था । जिस तरह के वाकयात हो रहे थे हमारे देश मे और दुनिया में, उनको देख कर मैं कुछ घबराया हुआ था । लेकिन सदर के खिताब के बाद और खास कर कुछ मुअज्जज मैम्बरों की तकरीरों को सुनने के बाद मैं मुस्तकबिल की तरफ बहुत ज्यादा यकीन के साथ देखने लगा हूं । मैं इसके लिए श्री ए० के० गोपालन, और श्री एच० एन० मुखर्जी का शुक्र गुजार हूं । मैं इंटरनेशनल सिचुएशन, सैक्युलरिज्म और आर्थिक स्वराज्य वगैरह बातो की चर्चा पहले करना चाहता था । लेकिन अब मैं हिन्दुस्तानी जम्हूरियत की चर्चा सबसे पहले करूंगा क्योंकि अगर हमारी जम्हूरियत जानदार नहीं है तो कोई भी बात मुमकिन नहीं होगी और ख्वाब जहा के तहां रह जायेंगे, उनकी तावीर किसी भी हालत मे मुमकिन नही होगी ।

17.25 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY in the Chair]

चेयरमैन साहब, अगर मैं आपको भुट्टो साहब की पहली तकरीर जब वह सदर हुए थे, याद दिलाऊं तो यह बात बहुत बेजगह न होगा । उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की सारी खराबी की जड़ यह थी कि "सरकार जनता की तरफ जवाबदेह नही थी ।"

"Government were not accountable to the people"

मैंने यह इसलिये कहा कि पाकिस्तान मे तो यह बात सिर्फ आज कही जा रही है लेकिन हमारे देश के पिछले पच्चीस बरसो की तवारीख ने उसी को बराबर अमली जामा पहनाया है । चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू मरहूम की सरकार रही हो या श्री लाल बहादुर शास्त्री मरहूम की सरकार रही हो या फिर चाहे हमारे मौजूदा वजीरे आजमा, श्रीमती इंदिरा गाधी, की सरकार हो । जनता ने सब से हिसाब मागा है और सारी सरकारों या उन पार्टियों को जिनकी सरकारें रही हैं सबको हिसाब देना पड़ा है । एक एक करके जनता ने सबसे हिसाब लिया है । जितनी पार्टिया हमारे देश में हैं, सबको जनता का जवाबदेह होना पड़ा है । जनता ने जब हमारी पार्टी के हिसाब को न माना तो हमारी पार्टी हार गई और श्री ए० के० गोपालन और उनके साथी, जो भी हों, उनकी पार्टी के हिसाब को जनता ने कहीं कहीं माना था और उनकी सरकारें कहीं कहीं पर बनीं । आज फिर एक बार जनता ने अपना फैसला हिसाब

देश कर दिया है तो मैं अर्ज करूंगा कि जनता का यह जो फैसला है इसको सबको मान लेना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता है कि श्री ए० के० गोपालन साहब को हमारी पार्टी और सरकार पर रंजिश क्यों होती है ? क्या उसका उन्हें पता नहीं है कि जब उन की पार्टी ने चुनाव जीता था तो उस वक्त भी चुनाव कराने का जिम्मा हमारी ही पार्टी की सरकार पर था और तब उनकी पार्टी ने सरकारें बनाई थीं चाहे मिली जुली सरकारें हों या उनकी अपनी पार्टी की सरकार हो । हम लोग ही उस वक्त हकूमत में थे । उस वक्त भी हम लोगों ने फेयर चुनाव कराये थे और अब भी कराये हैं । जो नतीजा अब सामने आया है उससे साफ जाहिर है कि जनता तोड़-फोड़ और खून खराबे की जिन्दगी से तंग आ चुकी थी । इन बातों पर चर्चा करने का मौका पार्लियामेंट को और भी मिलेगा लेकिन सारी बातों के बाद देश में जो कुछ भी हुआ है और यहां पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे खुशी हुई है कि हमारी जम्हूरियत बहुत जानदार है और उसका पानी बहुत तेज है । यह सब किसने किया ? इस देश की जनता ने ही तो किया ।

मैं बराबर ऐसा समझता रहा हूं कि इस देश के इंटेलेक्चुअलज नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी और मेहनतकश वीहिकल या एजंट आफ चेंज रही है । यह तो करिश्मा है हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की लीडरशिप का कि उन्होंने अपना मैंडेट उसी साधारण जनता से मांगा जिसको उन्हें जरूरत थी । इस तरह उन्होंने अपनी ताकत के सही स्रोत को पहचाना और जनता ने पूरी तरह सोच विचार करके अपना मैंडेट उनको दिया । आपने देखा ही है कि दूसरे लोग इस हिसाब किताब को देने में भूल कर गए तो उनके लिये मुनासिब यह था कि अपनी भूल की जांच पड़ताल करते न कि सदर के खिताब में कमजोरियों को खोजकर अपनी कमजोरियों को गलत करने की नाकाम कोशिश करते । अपने दामन में झांक कर देखते और इसको देखते कि उनमें कहां खामियां हैं, कहां कमजोरियां हैं, उन्होंने क्या गलतियां की हैं बजाय इसके कि सदर के खिताब में कमजोरियों को ढूंढने और अपनी कमजोरियों को छिपाने की नाकाम कोशिश करते ।

जनाबे सदर, चीन से हमारा देश तो दोस्ती चाहता ही है लेकिन उसने हमारी तरफ दुश्मनी का रवैया अख्त्यार कर रखा है । इस लड़ाई के बाद भी आपने देखा कि हमारी वजीरे आजम ने बार-बार कहा है कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की जनता के साथ दोस्ती चाहते हैं । एक बार नहीं, कई बार उन्होंने दोहराया है । आपने यह चीज अखबारों में पढ़ी होगी और तमाम प्लेटफार्म्ज पर उन्होंने इस बात को कहा है ।

लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख, और साथ साथ ताज्जुब तो अमरीका पर है कि वह एक जम्हूरी मुल्क होते हुए भी हम से जलाभुना बैठा है और हमसे ख्वाह-म-ख्वाह रंजिश रखता है । मेरे ख्याल में इसकी वजह सिर्फ यह है कि भारत ने अपने और इंडियन सबकान्टिनेंट के मफाद का ख्याल किया है । आज के जमाने में एक बात किसी भी देश को नहीं भूलनी चाहिये कि साइंटिफिक और टैकनालोजिकल एडवांस की वजह से दुनिया की तहज़ीब को भी एक नया डाइमेंशन मिला है, जो आब्सक्यूरेंटिस्ट नहीं हैं । और इस माहौल में सारे रिश्ते बराबरी की बुनियाद पर ही हो सकते है, ओवरलार्डशिप की बुनियाद पर हरगिज नहीं ।

मैं प्रधान मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि बंगला देश और दूसरे इन्टरनेशनल रिश्तों में उन्होंने इस मुल्क की गुमशुदा आइडेंटिटी को उजागर किया है । इसकी रोशनी में ध्यान देने की बात यह है कि जब तक दुनियां के कुछ दलों की ओवरलार्डशिप की नीति बनी रहेगी, तब तक दुनिया का कोई भी देश जो खुददार है और जो इज्जत की जिन्दगी बसर करना चाहता है उसे और उसके लिये खतरा बना रहेगा ।

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

और उस खतरे की तरफ सदरे-जम्हूरिया के खिताब में सही तौर पर ध्यान दिलाया गया है। इसलिये आज जरूरत है अपनी ताकत, यानी इंटरनल स्ट्रेंग्थ एन्ड स्टेबिलिटी की, सैल्फ रिलायेंस की। यह ठीक ही कहा गया है कि "इटर्नल विजिलेंस इज दि प्राइस आफ लिबर्टी।"

"गरीबी हटाओ" के आन्दोलन की कामयाबी के लिये मरकज और सूबों में मजबूत यानी स्टेबल सरकारों का फार्मेशन और दूसरे सोशियो-इकानोमिक स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, जिनका तजकिरा सदरे-जम्हूरिया की तकरीर में किया गया है। हम श्रीमती इंदिरा गांधी की लीडरशिप में ग्लोरी की एक चोटी से दूसरी चोटी पर गये हैं, तो उसकी एक वजह यह भी है कि देश को इकानोमिक लीडरशिप भी गलत नहीं मिली, जिसकी बिना पर हमारी हर जीत हार में तब्दील हो सकती थी। इन बातों पर चर्चा करने का मौका हमें आगे भी मिलेगा।

बंगलादेश की सरजमीन पर जो जंग हुई, वह जम्हूरियत की हिफाजत की लड़ाई ही नहीं थी, बल्कि सैकुलरिज्म की हिफाजत की लड़ाई भी थी। इंडियन सब-कान्टिनेंट में एक गलत बात 1947 में हुई थी। उस वक्त मजहब और धर्म के नाम पर मुल्क के टुकड़े हुए, दिलों के टुकड़े हुए, इन्सानियत के टुकड़े हुए और तवारीख का वह बोझ हम आज तक अपने कंधे पर ढोते आ रहे थे। यह जख्म भर भी सकता था, अगर पाकिस्तान के फौजी हुकमरानों ने अपनी जनता के दिलों की आवाज सुनी होती और अगर वे अपने उन दोस्तों के बहकावे में न आये होते, जिन्होंने उनको हथियार तो दिये, लेकिन जीने के सारे रास्ते बन्द कर दिये। क्योंकि पाकिस्तान की आंखों पर पट्टी बंधी थी कि वह अपने मफाद को नहीं देख सका। पाकिस्तान को नुकसान भारत से नहीं, बल्कि उन मुल्कों से पहुंचा है, जिन्होंने उसे हथियार दिये, जिनका उसने बेजा और गलत इस्तेमाल किया।

मैं मुसलमान हूं और आज मैं सदन के सामने, पार्लियामेंट के सामने, अपने दिल का एक पुराना दर्द खोल कर रखना चाहता हूं। क्या आपने उस इंसान के दिल की घुटन का अंदाजा किया है, जिसकी वफादारी पर उसके अपने ही मुल्क में शुबहा किया जाये, जिसकी तरफ शकूक की निगाह से देखा जाये? पिछले बीस बरसों से, जबसे मेरी सियासी जिन्दगी शुरू हुई है, मैं यह तकलीफ झेलता आ रहा हूं। मैं इस बात को जरा साफ करके अर्ज करना चाहता हूं। बंटवारे के बाद मुल्क के फिर्कापरस्त लोगों और जमाअतों ने एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया था कि देश में कम्युनलिज्म और फिर्कापरस्ती की ताकतों को ताकत मिली थी। कुछ लोग इससे गुमराह भी हुए। और अगर इस मुल्क में इस जजबाती आलिशजदगी के बाद भी कम्युनल हार्मनी का नक्शा और ढांचा ठीक-ठीक बना रहा, तो उसका क्रेडिट देश की लीडरशिप को—जो मरहूम महात्मा गांधी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक को—है।

बंगला देश में जो कुछ भी हुआ, उसने हमारे गले से तवारीख के उस खौफनाक बोझ को उतार फेंका है। मैं इस देश के मुसलमानों की तरफ से, और उनकी आने वाली नस्लों की तरफ से, आपके जरिये सदरे-जम्हूरिया को, उनकी सरकार को और सरकार की नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी, को खिराजे अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने हमें एक नेशनल आइडेन्टिटी दी और यह साबित कर दिया कि हमारी कौमी जिन्दगी मे फिर्कापरस्ती नहीं है, बल्कि वह एक साजिश है इस मुल्क की तरक्की के दुश्मनों की, अमन के दुश्मनों की, सोशलिज्म के दुश्मनों की।

वैसे, बंगलादेश में जो कुछ हुआ, वह तो मुसलमानों पर मुसलमानों के जुल्म की बात है। शेख मुजीबुर्रहमान की लड़ाई भी मुआशी-जुल्म और फिर्कापरस्ती के खिलाफ थी जम्हूरियत के लिये थी सैकुलरिज्म के लिये थी। अगर दुनिया के हिस्से में तरक्की होती है और एक ताकतवर, सैकुलर और खुशहाल समाज

को बनाता है, तो बंगला देश का तुलू और भारत और बंगला देश की दोस्ती एक नई सुबह की आवाज है, जिसका हम सब खैर-मकदम करते हैं।

सभी बातों का निचोड़ यह है कि हम लोगों ने अपने वजीरे आजम की लीडरशिप में जो कुछ पाया है, वह है यकीन और इसी बुनियाद पर मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कल हमारा है—टुमारो इज आवर्ज।

[شری محمد جمیل الرحمان (کشن گنج): معزز چیئرمین صاحب۔ پارلیمنٹ سے میری جان پہچان اور میری زندگی بہت تھوڑی اور چھوٹی ہے اس لئے میں نے سوچا تھا کہ آنریبل ممبرز کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدر جمہوریہ کے خطاب پر ایسے سبجیکٹ پر چرچہ کروں گا جس کے اوپر دھیان دینا ہماری قومی زندگی کی مضبوطی کے لئے میرے خیال میں ضروری تھا۔ جس طرح کے واقعات ہو رہے تھے ہمارے دیش میں اور دنیا میں ان کو دیکھ کر میں کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ لیکن صدر کے خطاب کے بعد خاص کر کچھ معزز ممبروں کی تقریروں کو سننے کے بعد میں مستقبل کی طرف مزید زیادہ یقین کے ساتھ دیکھنے لگا ہوں۔ میں نے سنا شری اے۔ کے گوپالن اور شری ایچ۔ این مکرجی کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں انٹرنیشنل سچویشن۔ سیکولرزم اور آرٹیکلز سوراجیہ وغیرہ باتوں کی چرچہ پہلے کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں ہندوستانی جمہوریت کی چرچہ سب سے پہلے کروں گا کیونکہ اگر ہماری جمہوریت جاندار نہیں ہے تو کوئی بھی بات ممکن نہیں ہوگی اور عوام جہاں کی تہاں رہ جائیں گے۔ ان کی ترقی کسی بھی حالت میں ممکن نہیں ہوگی۔

چیئرمین صاحب اگر میں آپ کے دھیان کو بھٹو صاحب کی پہلی تقریر جب وہ صدر ہوئے تھے یاد دلاؤں تو یہ بات بے جگہ نہ ہوگی۔ انھوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ساری خرابی کی جڑ یہ تھی کہ "سرکار جنتا کی طرف جواب دہ نہیں تھی۔

"Government were not accountable to the people".

میں نے یہ اس لئے کہا کہ پاکستان میں تو یہ بات صرف آج کہی جا رہی ہے لیکن ہمارے دیش میں پچھلے پچیس برسوں کی تاریخ نے اس کو برابر عملی جامہ پہنایا ہے۔ چاہے پنڈت جواہر لال نہرو مرحوم کی سرکار رہی ہو یا شری لال بہادر شاستری مرحوم کی سرکار رہی ہو یا چاہے ہمارے موجودہ وزیر اعظم شریمتی اندرا گاندھی کی سرکار رہی ہو۔ جنتا نے سب سے حساب مانگا ہے اور ساری سرکاروں یا ان پارٹیوں کو جن کی سرکاریں رہی ہیں سب کو حساب دینا پڑا ہے۔ ایک ایک کر کے جنتا نے سب سے حساب لیا ہے۔ جتنی پارٹیاں ہمارے دیش میں ہیں سب کو جنتا کا جواب دہ ہونا پڑا ہے۔ جنتا نے جب ہماری پارٹی کے حساب کو لیا تو ہماری پارٹی ہار گئی اور شری اے۔ کے گوپالن اور ان کے ساتھی جو بھی ہیں ان کی پارٹی کے حساب کو جنتا نے کہیں کہیں لیا تھا اور ان کی سرکاریں کہیں کہیں پر بنیں۔ آج پھر ایک بار جنتا نے اپنا فیصلہ حساب دیکھ کر دیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ جنتا کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو سب کو مان لینا چاہئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شری اے۔ کے گوپالن صاحب کو ہماری پارٹی اور سرکار پر رنجش کیوں ہوتی ہے۔ کیا اس کا پتہ انھیں نہیں ہے کہ جب ان کی پارٹی نے چناؤ جیتا تھا تو اس وقت بھی چناؤ کرنے کا ذمہ ہماری ہی پارٹی کی سرکار پر تھا۔ اور تب ان کی پارٹی نے سرکاریں بنائیں تھیں۔ چاہے ملی جلی سرکاریں ہوں یا ان کی اپنی پارٹی کی سرکار ہو۔ ہم لوگ بھی اس وقت حکومت میں تھے۔ اس وقت بھی ہم لوگوں نے فیئر چناؤ کرائے تھے۔ اور اب بھی کرائے ہیں جو نتیجہ اب سامنے آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جنتا توڑ پھوڑ اور خون خرابے کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ان باتوں پر چرچہ کرنے کا موقعہ پارلیمنٹ کو اور بھی ملے گا۔ لیکن ساری باتوں کے بعد دیش میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور یہاں پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہماری جمہوریت بہت جاندار ہے۔ اور اس کا پانی بہت تیز ہے۔ یہ سب کس نے کیا۔ اس دیش کی جنتا نے ہی تو کیا۔

میں برابر ایسا سمجھتا رہا ہوں کہ اس دیش میں اس دیش کے اسٹیبلیشرز نہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں بلکہ ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے اور محنت کش جنتا دیہکل یا ایجنٹ آف چینج رہی ہے۔ یہ تو کرشمہ ہماری پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی کی لیڈرشپ کا ہے کہ انھوں نے اپنا مینڈیٹ اس سادھارن جنتا سے مانگا جس کی انھیں ضرورت تھی۔ اس طرح انھوں نے اپنی طاقت کے صحیح سوتے کو پہچانا اور جنتا نے پوری طرح سوچ وچار کر کے اپنا مینڈیٹ ان کو دیا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ دوسرے لوگ اس حساب کتاب کو دینے میں بھول کر گئے تو ان کے لئے مناسب یہ تھا کہ اپنی بھول کی جانچ پڑتال کرتے نہ کہ صدر کے خطاب میں کمزوریوں کو کھوج کی اپنی کمزوریوں

کو غلط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ۔ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھتے کہ ان میں کہاں خامیاں ہیں ۔ کہاں کمزوریاں ہیں ۔ انھوں نے کیا غلطیاں کی ہیں ۔ بجائے اس کے کہ صدر کے خطاب میں کمزوریوں کو ڈھونڈنے اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ۔

جناب صدر ۔ چین سے ہمارا دیش تو دوستی چاہتا ہی ہے لیکن اس نے ہماری طرف دشمنی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ۔ اس لڑائی کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہماری وزیر اعظم نے بار بار کہا ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی جنتا کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں ۔ ایک بار نہیں ۔ کئی بار انھوں نے اس بات کو دہرایا ہے ۔ آپ نے یہ چیز اخباروں میں پڑھی ہوگی اور تمام پلیٹ فارمز پر اس بات کو کہا ہے ۔

لیکن مجھے سب سے زیادہ دکھ اور ساتھ ساتھ تعجب تو امریکہ پر ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہوتے ہوئے بھی ہم سے جلا بھنا بیٹھا ہے ۔ اور ہم سے خواہ مخواہ رنجش رکھتا ہے ۔ میرے خیال میں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھارت نے اپنے اور انڈین سب کونٹیننٹ کے مفاد کا خیال کیا ہے ۔ آج کے زمانے میں ایک بات کسی بھی دیس کو نہیں بھولنی چاہیئے کہ سائنٹفک اور ٹیکنولوجیکل ایڈوانس کی وجہ سے دنیا کی تہذیب کو بھی ایک نیا ڈائمینشن ملا ہے ۔ جو ابسکیورنٹسٹ نہیں ہے ۔ اور اس ماحول میں سارے رشتے برابری کی بنیاد پر ہی ہو سکتے ہیں ۔ اور لورڈشپ کی بنیاد پر ہرگز نہیں ۔

میں پردھان منتری کا شکر گزار ہوں کہ بنگلہ دیش اور دوسرے انٹرنیشنل رشتوں میں انھوں نے اس ملک کی گمشدہ آئیڈینٹٹی کو اجاگر کیا ہے ۔ اس کی روشنی میں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کچھ دیشوں کی اور لارڈشپ کی نیتی بنی رہے گی تب تک دنیا کا کوئی بھی دیس جو خوددار ہے اور جو عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے اور اس کے لئے خطرہ بنا رہے گا ۔ اور اس خطرے کی طرف صدر جمہوریہ کے خطاب میں صحیح طور پر دھیان دلایا گیا ہے ۔ اس لئے آج ضرورت ہے اپنی طاقت ۔ یعنی انٹرنل سٹرنگتھ اینڈ سٹیبلیٹی کی سیلف ریلائینس کی ۔ یہ ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ اٹرنل ویجیلینس از دی پرائس آف لبرٹی ۔

غریبی ہٹاؤ کے اندولن کی کامیابی کے لئے مرکز اور صوبوں میں مضبوط یعنی سٹیبل سرکاروں کا فارمیشن اور دوسرے سوشیو اکونومک سٹیپ بہت ضروری ہیں ۔ جن کا تذکرہ صدر جمہوریہ کی تقریر میں کیا گیا ہے ۔ ہم شریمتی اندرا گاندھی کی لیڈرشپ میں گلوری کی ایک چوٹی سے دوسری چوٹی پر گئے ہیں ۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیش کو اکنومک ۔ لیڈرشپ بھی غلط نہیں ملی ۔ جس کی بنا پر ہماری ہر جیت ہار میں تبدیل ہو سکتی تھی ۔ ان باتوں پر چرچہ کرنے کا موقعہ ہمیں آگے بھی ملے گا ۔

بنگلہ دیش کی سرزمین پر جو جنگ ہوئی وہ جمہوریت کی حفاظت کی لڑائی ہی نہیں تھی ۔ بلکہ سیکولرزم کی حفاظت کی لڑائی بھی تھی ۔ انڈین سب کونٹیننٹ میں ایک غلط بات ۱۹۴۷ میں ہوئی تھی اس وقت مذہب اور دھرم کے نام پر ملک کے ٹکڑے ہوئے ۔ دلوں کے ٹکڑے ہوئے ۔ انسانیت کے ٹکڑے ہوئے ۔ اور تاریخ کا وہ بوجھ ہم آج تک اپنے کندھے پر ڈھوتے آ رہے تھے ۔ یہ زخم بھر بھی سکتا تھا ۔ اگر پاکستان کے فوجی حکمرانوں نے اپنی جنتا کے دلوں کی آواز سنی ہوتی ۔ اور اگر وے اپنے ان دوستوں کے بہکاوے میں نہ آئے ہوتے ۔ جنھوں نے ان کو ہتھیار تو دیئے لیکن جینے کے سارے راستے بند کر دیئے کیونکہ پاکستان کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی تھی کہ وہ اپنے مفاد کو نہیں دیکھ سکا ۔ پاکستان کو نقصان بھارت سے نہیں بلکہ ان ملکوں سے پہنچا ہے جنھوں نے اسے ہتھیار دیئے ۔ جس کا اس نے بیجا اور غلط استعمال کیا ۔

میں مسلمان ہوں اور آج میں سدن کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے اپنے دل کا ایک پرانا درد کھول کر رکھنا چاہتا ہوں ۔ کیا آپ نے اس انسان کے دل کی گھٹن کا اندازہ کیا ہے جس کی وفاداری پر اس کے اپنے ہی ملک میں شبہ کیا جائے ۔ جس کی طرف شکوک کی نگاہ سے دیکھا جائے ۔ پچھلے ۲ برسوں سے جب سے میری سیاسی زندگی شروع ہوئی ہے ۔ میں یہ تکلیف جھیلتا آ رہا ہوں ۔ میں اس بات کو ذرا صاف کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں ۔ بٹوارے کے بعد ملک کے فرقہ پرست لوگوں اور جماعتوں نے ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ دیش میں کمیونلزم اور فرقہ پرستی کی طاقتوں کو طاقت ملی تھی ۔ کچھ لوگ اس سے گمراہ بھی ہوئے اور اگر اس ملک میں اس جذباتی آتش زدگی کے بعد بھی کمیونل حامین کا نقشہ اور ڈھانچہ ٹھیک ٹھاک بنا رہا ۔ تو اس کا کریڈٹ دیش کی لیڈرشپ کو جو مرحوم مہاتما گاندھی سے لیکر شریمتی اندرا گاندھی تک کو ہے ۔

بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا اس نے ہمارے گلے سے تاریخ کے اس خوفناک بوجھ کو اتار پھینکا ہے ۔ میں اس دیش کے

مسلمانوں کی طرف سے اور ان کی آنے والی نسلوں کی طرف سے آپ کے ذریعے صدر جمہوریہ کو ان کی سرکار کو اور سرکار کی نیتا شریمتی اندرا گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جنھوں نے ہمیں ایک نیشنل آئیڈینٹیٹی دی، اور یہ ثابت کر دیا کہ ہماری قومی زندگی میں فرقہ پرستی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک سازش ہے اس ملک کی ترقی کے دشمنوں کا امن کے دشمنوں کا شوشلزم کے دشمنوں کا۔

ویسے بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ تو مسلمانوں پر مسلمانوں کے ظلم کی بات ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کی لڑائی معاشی ظلم اور فرقہ پرستی کے خلاف تھی۔ جمہوریت کے لئے تھی۔ سیکولرزم کے لئے تھی۔ اگر دنیا کے اس حصے میں ترقی ہوتی ہے اور ایک طاقتور سیکولر اور خوش حال سماج کو بننا ہے تو بنگلہ دیش کا طلوع اور بھارت اور بنگلہ دیش کی دوستی ایک نئی صبح کی آغاز ہے۔ جس کا ہم سب خیر مقدم کرتے ہیں۔

سبھی باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے وزیر اعظم کی لیڈرشپ میں جو کچھ پایا ہے وہ ہے یقین اور اسی بنیاد پر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل ہمارا ہے "ٹومارو از اورز"]

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : Sir, I have given some amendments to the Motion of Thanks and I shall speak on some of them. But before doing so, I would like to congratulate the Prime Minister on the wonderful leadership she gave to our country during the last Indo-Pak war. I also congratulate our Defence Minister who did a wonderful job So do I congratulate our distinguished Army, Navy and Air Chiefs who set up a record in military history by winning this war in the short space of 13 days. The number of prisoners of war taken by us is another record. I had known that Gen. Rommel's forces had taken the largest number of prisoners of war ever taken, about 40,000 in North Africa but our Generals have surpassed that record in the number they have taken which exceeded 93,000.

By liberating Bangla Desh, the course of history has been changed. President Nixon and Chairman Mao Tse-tung are passing sleepless nights. I am very happy that the stature of our nation has risen and we have solved many problems as a result of the liberation of Bangla Desh. Pakistan is no longer the danger that it was formerly and those difficulties which we used to have from that quarter are no longer there. I, therefore, agree with the President who has praised the Prime Minister and the Armed Forces for this great victory. I am also happy that the Prime Minister has swept the country in the recent State Assembly elections. She cannot now have any excuse for not fulfilling her promise of *Garibi Hatao*. She has to fulfil that promise. I only wish to warn that if that promise is not fulfilled then there will be a set-back and people will be disillusionned. I am sure that she will do what she has promised and *Garibi Hatao* will become a reality to an appreciable extent.

The most difficult problem of unemployment which has become a sort of cancer in our body politic. If we can solve that problem, we can remove the biggest trouble that faces our country.

Coming to land reforms, we have been promised many times that land will be distributed to the landless. That has not yet been done and no step has been taken in that direction. I have read in the papers that many State chiefs have promised to give land reforms first priority in their programmes. I only wish they do it. Land distribution is possible only when we reduce the ceiling and distribute the surplus land among the landless. I hope it will be done.

Then I come to the treatment of labour. As a trade union worker, I am particularly anxious about the sugar factory labour. The second wage board was due to give its report in 1965. But it gave its report four years afterwards in 1969. The third wage board was due to be appointed in 1970. But it has not yet been appointed. I, therefore, urge that the third wage board for the sugar industry should be appointed immediately and should be asked to report as soon as possible so that justice may be done to the sugar factory workers, who are getting very poor wages. While a steel factory worker gets a minimum wage of Rs. 240 and a jute factory worker gets Rs. 200, a sugar factory worker gets only Rs. 150, which is not just or proper.

The sugar industry workers have to go without any employment for six months in the year. There has not been any provision for making them some payment during this off-season. I hope this problem will be tackled and the sugar industry workers will be given half their salary during the period when they are without any employment.

The problems of the sugar industry cannot

[Prof. S. L. Saxena]

be solved unless it is nationalised. I think it was during the Bombay session of the Congress in December, 1969 that a resolution was passed for the nationalisation of the sugar industry in UP. Though three years have passed, no step has been taken in that direction. In fact, people are becoming very much disappointed and they do not know whether that promise will be fulfilled or not. So many promises have been made by so many Chief Ministers that it will be nationalised, but it has still not been done. What is the result ? The result is that every sugar factory owner has removed all the valuable machinery from the factory and sold it in the market, leaving only the junk there. In fact, the machinery is not being repaired properly with the result that there are so many break-downs during the season. If the sugar industry is not nationalised in the near future, I am sure the factories will not be able to work. You either say that you will nationalise it or you announce that you will not nationalise it. If you say that you will not nationalise it, then the factory owners will put in money and repair the machinery. Now the position is very bad because of the uncertainty. So. that uncertainty should be removed.

The sugarcane growers have not had their due. They have been given only an increase to Rs. 10 per quintal after some time whereas the price of sugar has gone up very much This is not fair. The cane growers should also get the benefit of the increase in sugar prices. I feel that some bonus should be given to the sugar workers and sugar cane growers as their share in the higher price realised.

An average of sugar price realised may be found out and the workers and growers paid bonus accordingly.

There was recently an announcement that sugar will be controlled so that the prices come down. But that has not yet been done. I hope, this will be done.

MR. CHAIRMAN : The Minister of Foreign Trade will make a statement at 5.55 P.M.

Shri Shashi Bhushan.

श्री शशिभूषण (दिल्ली दक्षिण) : सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया लेकिन साथ-साथ यह भी उनको थोड़ा संशय हुआ कि प्रधान मंत्री तानाशाह बनती जा रही है। मुझे लगता ऐसा है कि जो लोग स्वयं एक ऐसी संस्था पर विश्वास करते हों जो एक धर्म, एक गुरु, एक राष्ट्र पर विश्वास करती हो, सुबह से शाम तक 30 साल परेड करने के बाद आज उन्हे हिन्दुस्तान की लोकतंत्र से चुनी हुई नेता इंदिरा गांधी में तानाशाही नजर आती है . .(**व्यवधान**) . ..यही कहा है उन्होंने, देख लीजिए आप। मुझे ठीक अन्दाज है जो कुछ उन्होंने कहा है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के भाषण का मैं समर्थन करता हूं और मुझे वह दिन भी याद आता है जब गिरि जी के समर्थन मे सबसे पहले अपनी पार्टी मे मैंने कहा था कि आत्मा की आवाज के मुताबिक सदस्यों को वोट देने का अधिकार मिले, और उस वक्त हमारी पार्टी ने हमारे नेता ने, लोगों का आत्मा की आवाज के मुताबिक वोट देने का अधिकार दिया। गिरि साहब जीते और हमें फख्र है कि हमारे देश मे एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जो सही मानों मे प्रजातंत्र, लोकतंत्र और समाजवाद पर विश्वास करता है। कहीं इत्तफाक से संजीव रेड्डी जीत गए होते जिनके खिलाफ मेरी आत्मा की आवाज जागी थी, अभी अटल बिहारी जी ने यह कहा कि अब कांग्रेस लोगो को इधर से उधर संस्था छोड़ने तथा आया राम गया राम बनने मे मदद न करे, हालांकि हमने ऐसा कभी नही किया, उस वक्त संजीव रेड्डी जिन लोगों से हाथ मिला रहे थे और देश मे अंदर-अंदर एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात कर रहे थे, उसमे जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस (ओ) को मिलाकर इस देश में वह एक राष्ट्रीय सरकार बनाने का षडयंत्र कर रहे थे, अगर वह षडयंत्र कहीं पूरा हो गया होता तो क्या इस देश में प्रजातंत्र रहता ? क्या बंगला देश आजाद हो सकता था ? क्या बंगला देश हिन्दुस्तान के सम्प्रदायवादियों से, अमरीकी एजेन्टों से जो दिल्ली के तख्त पर बैठे

होते उनसे मदद मांग सकता था ? आज चूंकि हिन्दुस्तान में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र से चुनी हुई मजबूत सरकार है, इसीलिए मुजीबुर्रहमान, उनकी पार्टी और उनके साथियों ने हमसे मदद मांगी और हमने मदद दी। वह आजाद हुए। कहा गया कि हमने देर से मान्यता दी। बगला देश को खास तौर से अटल बिहारी जी ने कहा। मैं कहना चाहता हू कि जिस दिन से रिफ्यूजीज आए उस दिन से ही उन फटे चिथड़े पहने हुए लोगो को किसने प्रेरणा दी ? एक लाख बगाली नौजवानो को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिग दी, दुनिया के इतिहास मे इतने थोड़े समय मे इतने लोगो को ट्रेनिग देना बहुत बड़ी बात है, उनको ट्रेनिग दी और उसके बाद उन्होने अपने यहा बगला देश जा कर चक्रव्यूह रचा, उनको उसमे हमने सहायता दी और वह आजाद हुए। एक तरफ तो आजादी के लिए उनके नौजवान तैयारी कर रहे थे, देश की सारी राष्ट्रीय शक्ति बगला देश के अदर जाकर मदद कर रही थी .

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, व्यवस्था सवाल है, सदन मे गणपूर्ति नही है।

सभापति महोदय . घन्टी बज रही है अब कोरम हो गया है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री शशि भूषण : सभापति महोदय, एक तरफ देश की सारी प्रगतिशील शक्तिया बगला देश के अन्दर जाकर उनकी मदद कर रही थी, क्या कोई जनसघी या कोई साम्प्रदायवादी बंगला देश मे गया, कोई भी जा नही सकता था। सभापति महोदय, एक तरफ बंगला देश के नौजवानों को गुरिल्ला-वार-फेअर की ट्रेनिंग दी जा रही थी, दूसरी तरफ सारे विश्व में उनके लिये समर्थन तैयार किया जा रहा था। अगर उनको हमने समर्थन न दिया होता तो बंगला देश की पालियामेन्ट के मेम्बरों को कैसे बाहर आने दिया जाता, उनको कौन पासपोर्ट देता था ? क्या महारानी सिन्धिया देती थीं ? विश्व मे पाकिस्तान के दूतावासों से जो बंगाली राजदूत इस्तीफा दे कर बाहर आते थे, उनकी कौन सहायता करता था, क्या जनसंघ सहायता करती थी ? सारे देश ने उनको हृदय से मान्यता दी।

दूसरी तरफ जब जेम्ज बाण्ड 007—मि० किसीगर हिन्दुस्तान आये उस वक्त एक प्रतिक्रियावादी वातावरण हिन्दुस्तान में तैयार किया जा रहा था। उस समय अटल जी कह रहे थे कि देश के साथ कोई नही है, देश अकेला है, गर्क होने वाला है। उस वक्त उस माहौल में एक आखरी धक्का देने के लिये जेम्ज बाण्ड मि० किसीगर पाकिस्तान से चुपचाप चीन चले गये, चीन के साथ दोस्ती का एलान कर दिया। उस समय जनसंघ ने यहां एक सत्याग्रह शुरू किया। वे राजे-महाराजे सत्याग्रह करने गये, जिन्होंने अपने राज्य मे आजादी के सत्याग्रहियों को कोडों से पीट कर, घसीट कर मारा था, उस समय सुबह से शाम तक उन स्वतंत्रता सत्याग्रहियो को कोई माला पहनाने वाला नहीं था। आज ये नाटकीय सत्याग्रही सुबह से शाम तक दूध पीकर हवालात मे बाहर आ गये, एक क्रान्ति हो गई—इस तरह का तमाशा किया। पाकिस्तान रेडियो शोर करता था कि हिन्दुस्तान की सरकार का तख्ना हिल रहा है, सत्याग्रह शुरू हो रहा है।

जिस समय देश मे एक शानदार वातावरण तैयार हो रहा था, हम बगला देश के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर, नयी क्रांति की तैयारी कर रहे थे, हमारे लोग उन क्रान्तिकारियों के साथ बगला देश के अन्दर जा रहे थे, उस समय इनके नेता सिर्फ बार्डर तक हो कर आगये और उसके बाद इतनी घृणित बात हुई—कलकत्ता के अन्दर उस जमाने में आर्यसमाज का एक बड़ा जल्सा किया गया और वहां कहा गया कि जो मुस्लिम रिफ्यूजी आ रहे हैं, उनको हिन्दू बनाया जाय—इससे ज्यादा विश्वासघात और क्या हो सकता है। जिस समय सारा हिन्दुस्तान—हिन्दू, मुस्लिम, सिख सब मिलकर बंगला देश के लिये लड़ रहे थे,

[श्री शशि भूषण]

उस समय कलकत्ता के बड़े बाजार में एक प्रतिक्रियावादियों का जल्सा हो रहा था और उसमें इनके बड़े नेता—अटल जी—वहां विराजमान थे···

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : यह गलत बात है। (**व्यवधान**)

श्री शशि भूषण : मैंने खुद सुना है।

सभापति महोदय, जहां तक जेम्ज बाण्ड, मि० किसींगर का सवाल है, यहां सत्याग्रह कराया, चीन के साथ दोस्ती करके सोचा था कि धक्का लगेगा भारत को, लेकिन इसी बीच में रूस के साथ शान्ति संधि हो गई।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें। श्री एल० एन० मिश्र।

17.55 hrs.

STATEMENT *Re.* TRADE AGREEMENT BETWEEN INDIA AND BANGLA DESH

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : I am glad to inform the House that a Trade Agreement has been concluded between India and Bangla Desh following talks yesterday with a delegation led by His Excellency Mr. M. R Siddiqui, Minister of Trade and Commerce, Government of the people's Republic of Bangla Desh. The agreement came into force immediately and will remain in force, in the first instance; for a period of one year. A copy of the Agreement has been placed in the Parliament Library.

It aims at the expansion and promotion of trade between the two countries on the basis of mutul advantage.

It is set within the framework of the Joint Statement of the Prime Ministers of India and Bangla Desh where it was recognised that the common people of both countries should be the beneficiaries of close co-operation between the two Governments in the fields of trade and development.

There will be three tiers of trade consisting of :

(i) A border Trade Arrangement which would facilitate trade in perishable commodities and articles of daily use to meet the requirements of people living in rural areas on either side of the land customs frontiers. These facilities will be available to persons holding special permits, living within sixteen kilometers on the border on either side.

(ii) To meet transitional needs of Bangla Desh the two Governments have agreed to an interim arrangement under which import and export of specified commodities and goods of special interest to the two countries, produced and manufactured in the two countries, will be facilitated on a balanced basis to the extent of Rs. 25 crores each way. Supplies from India to Bangla Desh will cover *inter alia* cement, coal, unmanufactured tobacco, cotton yarn, asphalt, *etc.* Items for import from Bangla Desh under such balance trade includes fresh fish, raw jute, newsprint, furnace oil, jute, batching oil and naphtha, *etc.* Transactions will be routed through a special account operated by the State Bank of India, Calcutta and a bank to be designated by the Government of Bangla Desh

(iii) The two Governments have agreed that imports and exports of commodities which are not covered under the balancing arrangement, shall be permitted in accordance with the normal rules and regulations of the either country.

The two Governments have also agreed to make mutually beneficial arrangements for the use of their waterways, railways and roadways for commerce between the two countries and for the passage of goods between two places in each country through the territory of the other. The two countries would accord to the commerce of each other the Most Favoured Nation Treatment.